



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 23 अगस्त, 2006/1 भाद्रपद, 1928

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 23 अगस्त, 2006

संख्या वि० स०-विधायन-गवर्न. बिल/1-45/2006.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2006 (2006 का विधेयक संख्यांक 16) जो आज दिनांक 23-8-2006 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में

पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाजटा,
सचिव ।

हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2006

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, धार्मिक, पूर्त या अन्य सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण और कार्यकरण का उपबन्ध करने के लिए विधि पुनः अधिनियमित करने तथा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21), जहां तक कि यह हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू है, को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय-1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण संक्षिप्त नाम, अधिनियम, 2006 है।

प्रारम्भ और
लागू होना।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

(3) यह अधिनियम निम्नलिखित सभी प्रयोजनों के लिए या उनमें से किसी के लिए बनाई गई सोसाइटियों को लागू होगा, अर्थात्:-

- (i) विज्ञान, शिक्षा, साहित्य या ललित कलाओं का संवर्धन;
- (ii) उपयोगी जानकारी का प्रसार ;
- (iii) राजनैतिक जानकारी का प्रसार ;
- (iv) सदस्यों के साधारण उपयोग के लिए या जनता के लिए खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों की संस्थापना और अनुरक्षण;
- (v) रंगचित्र वीथियों (गैलरीज) और अन्य कला संकर्मों की स्थापना और अनुरक्षण;
- (vi) लोक संग्रहालयों की स्थापना और अनुरक्षण;
- (vii) प्राकृतिक इतिहास, यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, उपकरणों या परिकल्पनाओं का संग्रहण;

- (viii) समाज कल्याण का संवर्धन;
- (ix) सेना अनाथों के कल्याण, राजनैतिक उपहृत व्यक्तियों के कल्याण तथा इन जैसे ही व्यक्तियों के कल्याण के लिए निधियों की स्थापना सहित धार्मिक या पूर्त प्रयोजन का संवर्धन;
- (x) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों का संवर्धन और कार्यान्वयन ;
- (xi) वाणिज्य, उद्योगों और खादी का संवर्धन; और
- (xii) ग्रामीण विकास का संवर्धन।

परिभाषाएँ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) “कलक्टर” से किसी जिला के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत होगा और इसके अन्तर्गत उपायुक्त भी होगा;
- (ख) “परिवार” से पति, पत्नी और उनके अविवाहित पुत्र और पुत्रियाँ अभिप्रेत हैं;
- (ग) “वित्तीय वर्ष” से प्रथम अप्रैल को प्रारम्भ होने वाला वर्ष अभिप्रेत होगा;
- (घ) “साधारण निकाय” से सोसाइटी के सभी सदस्य अभिप्रेत हैं;
- (ङ) “साधारण बैठक” से किसी सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक अभिप्रेत है और विशेष साधारण बैठक भी इसके अन्तर्गत है;
- (च) “शासी निकाय” से इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन निर्वाचित शासी निकाय अभिप्रेत है और जो इसके विनियम के अधीन सोसाइटी के प्रबन्धन से तत्समय न्यस्त है;
- (छ) “सरकार” या “राज्य सरकार” से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ज) “सोसाइटी का सदस्य” से वह व्यक्ति, जिसे सोसाइटी में इसके विनियमों के अनुसार प्रवेश दिया गया है, तत्समय सोसाइटी का सदस्य बना रहता है और जिसने सोसाइटी के विनियमों के अनुसार,—
 - (i) अभिदान संदत्त किया है;
 - (ii) सदस्यों की नामावली या सूची में हस्ताक्षर किए हैं;
 - (iii) जिसने त्याग-पत्र नहीं दिया है।

- (झ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ञ) “रजिस्ट्रार” से धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त सहायक सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उक्त धारा की उप-धारा (2) के अधीन सोसाइटियों के अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक रजिस्ट्रार भी हैं जब रजिस्ट्रार की किन्हीं या सभी शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग या पालन कर रहे हों;

- (ट) “विनियमों” या “उप-विधियों” से तत्समय प्रवृत्त सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत विनियम या उप-विधियां अभिप्रेत हैं;
- (ठ) “सोसाइटी” से इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है; और
- (ड) “राज्य सहायता प्राप्त सोसाइटी” से वह सोसाइटी अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निकाय या भारत या भारत से बाहर स्थित किसी अन्य अभिकरण से सहायता, अनुदान या ऋण प्राप्त करती है या किया है या रियायती दरों पर भूमि, भवन या दोनों तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त की हैं।

अध्याय-2

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी

3. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति, जिसे सोसाइटियों का रजिस्ट्रार कहा जाएगा, को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त है और ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के अधीन, जैसे राज्य सरकार करे, प्रशासन का अधीक्षण करेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करेगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी ही अधिसूचना द्वारा व्यक्तियों को, जिन्हें सोसाइटियों के अतिरिक्त, संयुक्त, उप और सहायक रजिस्ट्रार कहा जाएगा, ऐसे क्षेत्रों के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नियुक्त कर सकेगी और उन्हें इस अधिनियम के समस्त उपबन्धों या उनमें से किसी के अधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त कर सकेगी।

अध्याय-3

रजिस्ट्रीकरण

4. इस अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) में यथा वर्णित किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक या पूर्ण प्रयोजन के लिए सहयुक्त कोई सात या अधिक व्यक्ति जो विभिन्न कुटुम्ब के सदस्य और भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने को सक्षम हों, संगम ज्ञापन पर अपने नाम हस्ताक्षरित करके और उसे रजिस्ट्रार के पास दाखिल करके इस अधिनियम के अधीन अपने आप को सोसाइटी के रूप में गठित कर सकेंगे।

संगम के ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण द्वारा सोसाइटियों का बनाया जाना।

संगम के
ज्ञापन की
अपेक्षाएं।

5. (1) प्रत्येक सोसाइटी के संगम ज्ञापन में निम्नलिखित बातें होंगी—

- (i) सोसाइटी का नाम;
- (ii) सोसाइटी के उद्देश्य;
- (iii) सोसाइटी के मुख्य कार्यालय की अवस्थिति;
- (iv) व्यवस्थापकों (गवर्नरज), परिषद् निदेशकों या शासी निकाय जिन्हें सोसाइटी के विनियमों द्वारा इसके कार्यकलापों का प्रबन्धन न्यस्त है, के नाम, आयु, पता और उपजीविका।

(2) संगम के ज्ञापन में किसी भी ऐसे नाम का प्रस्ताव नहीं किया जाएगा—

(क) जो उस नाम जिसके द्वारा कोई विद्यमान सोसाइटी राज्य में कहीं भी पूर्वतन रजिस्ट्रीकृत है के समरूप हो या के अत्यधिक सदृश हो; या

(ख) जिसमें इसके संघटक के रूप में—

- (i) ऐसे शब्द हैं जो भारत सरकार या राज्य की सरकार का प्रतिश्रय इंगित करे या इंगित करने की प्रकल्पना करते हैं; या
- (ii) राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय या सर्वव्यापी महत्व के या ऐसे अन्य शब्द हैं जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; या
- (iii) ऐसे शब्द हैं जिनसे, रजिस्ट्रार की राय में, जनसाधारण को भ्रमित होने की संभावना है।

(3) सोसाइटी के विनियमों की एक प्रति, जो शासी निकाय के सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रति के रूप में प्रमाणित हो, संगम ज्ञापन के साथ दाखिल की जाएगी।

(4) व्यक्ति जिनके द्वारा या जिनकी ओर से ऐसा ज्ञापन दाखिल है, सोसाइटी से सम्बन्धित ऐसी और जानकारी, जैसी रजिस्ट्रार अपेक्षा करे, देंगे।

रजिस्ट्रीकरण।

6. यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि सोसाइटी ने इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया है और इसके प्रस्तावित विनियम उक्त उपबन्धों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह सोसाइटी और इसके विनियमों को ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, रजिस्टर करेगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

7. रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र इस बात का रजिस्ट्रीकरण निश्चायक साक्ष्य होगा कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

8. सोसाइटी के विनियम निम्नलिखित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे,—

सोसाइटी के विनियम।

- (i) सदस्यों के प्रवेश की शर्तें ;
- (ii) कतिपय परिस्थितियों के अधीन जुर्मानों और समपहरणों के लिए सदस्यों का दायित्व;
- (iii) किसी अभिदान या जुर्माने का संदाय न करने, सदस्यों के पदत्याग और निष्कासन के परिणाम ;
- (iv) कर्मचारिवृन्द और अधिकारियों की नियुक्ति और उनको हटाना तथा उनकी शक्तियां;
- (v) शासी निकाय को निर्वाचित करने और हटाने की रीति और ऐसे निकाय की शक्तियां ;
- (vi) सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक और अन्य बैठकों का समय और स्थान ;
- (vii) रीति जिसमें ऐसी बैठकों का नोटिस दिया जा सकेगा;
- (viii) सोसाइटी की बैठकों में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति ;
- (ix) विनियमों को बनाने, परिवर्तन करने और विखंडित करने की रीति;
- (x) निधियों का विनिधान (निवेश), लेखों का रख-रखाव और लेखों की वार्षिक या कालिक लेखा परीक्षा करना ;
- (xi) सोसाइटी का विघटन करने की रीति ;
- (xii) शर्त के लिए कि सोसाइटी का न तो कोई लाभ हेतु होगा न ही इसके लाभ को सदस्यों के बीच वितरित किया जाएगा ;
- (xiii) विघटन के पश्चात् अवधारित करना कि सम्पत्ति का सरकार द्वारा धारा 48 के अनुसार उपयोग किया जाए;
- (xiv) उप-विधियों द्वारा उपबन्धित किए जाने वाले मामले और रीति जिसमें वे बनाई जाएंगी ; और
- (xv) ऐसे अन्य विषय जो सोसाइटी की प्रकृति और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए समीचीन समझे जाएं।

9. (1) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के संगम ज्ञापन या विनियमों का कोई संशोधन तब तक विधिमन्य नहीं होगा, जब तक कि संशोधन इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत न कर दिया गया हो।

रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ज्ञापन या विनियमों या उप-विधियों

(2) ऐसे संशोधन हेतु प्रत्येक प्रस्ताव, ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रार को अग्रेषित किया जाएगा और यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि संशोधन इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है, तो वह, यदि उचित समझे, संशोधन को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के संगम ज्ञापन में या विनियमों में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि ऐसा प्रस्ताव ऐसे प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच बहुमत द्वारा अनुमोदित नहीं है।

(4) जहां कोई संशोधन उप-नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, वहां रजिस्ट्रार सोसाइटी को ऐसी फीस, जैसी विहित की जाए, के संदाय पर, उसके द्वारा अनुप्रमाणित संशोधन की एक प्रति जारी करेगा जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि यह सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

(5) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक 1860 का 21 सोसाइटी, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर इस अधिनियम और तदधीन बनाए उपबन्धों के अनुरूप उप-विधियां बनाएगी :

परन्तु यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है तो वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए नब्बे दिन से अनधिक की और अवधि अनुज्ञात कर सकेगा।

सोसाइटी के नाम में परिवर्तन । 10. धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन कोई भी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई की सहमति से इस प्रयोजन के लिए बुलाई गई साधारण बैठक में प्रस्ताव द्वारा इसके नाम में परिवर्तन कर सकेगी।

नाम में परिवर्तन का नोटिस । 11. (1) धारा 10 के अधीन पारित संकल्प की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी।

(2) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि नाम के परिवर्तन की बाबत इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है और प्रस्तावित नाम धारा 5 की उप-धारा (2) और (3) के उपबन्धों के अनुरूप है, तो वह रजिस्टर में पूर्व नाम के स्थान पर नए नाम की प्रविष्टि करेगा और उसमें सन्निविष्ट आवश्यक परिवर्तनों सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा और नाम का परिवर्तन ऐसे प्रमाण-पत्र के जारी करने पर ही पूर्ण और प्रभावी होगा।

(3) रजिस्ट्रार सोसाइटी के संगम ज्ञापन में भी आवश्यक परिवर्तन करेगा।

(4) रजिस्ट्रार उप-धारा (2) के अधीन जारी किसी प्रमाण-पत्र की प्रति के लिए ऐसी फीस प्रभारित करेगा जैसी विहित की जाए और इस प्रकार संदत्त समस्त फीस सरकारी खजाना में जमा (निक्षिप्त) की जाएगी।

12. सोसाइटी के नाम में परिवर्तन से न तो उन सदस्यों के किन्हीं अधिकारों नाम में या बाध्यताओं पर प्रभाव पड़ेगा जो सोसाइटी के नाम परिवर्तन से पूर्व प्रविष्ट (गृहीत) परिवर्तन का थे या न इससे सोसाइटी के द्वारा या के विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही त्रुटिपूर्ण हो प्रभाव। जाएगी।

13. जब कभी किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, जो किसी विशिष्ट प्रयोजन या सोसाइटियों प्रयोजनों के लिए स्थापित की गई है, के शासी निकाय को प्रतीत हो कि ऐसे प्रयोजन को इस अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत किन्हीं अन्य प्रयोजनों में या उनके लिए परिवर्तित, को अपने प्रयोजनों को विस्तारित या न्यून करना उपयुक्त होगा तब ऐसा शासी निकाय उस प्रस्थापना को परिवर्तित, विस्तारित या लिखित या मुद्रित रिपोर्ट के रूप में सोसाइटी के सदस्यों को प्रस्तुत (निवेदित) कर न्यून करने के सकेगा और सोसाइटी के विनियमों के अनुसार उस पर विचार करने के लिए विशेष लिए समर्थ साधारण बैठक बुला सकेगा : बनाना।

परन्तु ऐसी कोई प्रस्थापना, तब तक कार्यान्वित नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसी रिपोर्ट उस पर विचार करने के लिए शासी निकाय द्वारा बुलाई गई विशेष साधारण बैठक के दस दिन पूर्व सोसाइटी के हर एक सदस्य को परिदत्त नहीं कर दी जाती या डाक द्वारा नहीं भेज दी जाती और जब तक ऐसी प्रस्थापना के प्रति सहमति, सदस्यों के तीन बटा पांच मतों द्वारा जो स्वयं या परोक्षी के माध्यम से परिदत्त किए गए हों, नहीं दे दी जाती और पूर्ववर्ती बैठक के पश्चात् एक मास के अन्तराल से शासी निकाय द्वारा बुलाई गई दूसरी विशेष साधारण बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच मतों द्वारा पुष्ट नहीं कर दी जाती है।

14. प्रत्येक सोसाइटी उस नाम से, जिसके अधीन वह रजिस्ट्रीकृत है, एक सोसाइटी निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, और उसे निगमित का निगमित स्थावर और जंगम दोनों प्रकार की सम्पत्ति को अर्जित, धारित और व्ययन करने, संविदा निकाय करने, वादों और अन्य विधिक कार्यवाहियों को संस्थित करने और प्रतिवाद करने की होना। तथा उस प्रयोजन के लिए, जिसके लिए इसका गठन किया गया है, अन्य सभी आवश्यक बातें करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

अध्याय-4

सोसाइटी का प्रबन्धन, सदस्य के अधिकार तथा विशेषाधिकार

सोसाइटी
का शासी
निकाय।

15. (1) प्रत्येक सोसाइटी धारा 19 के अधीन हुई सोसाइटी की वार्षिक साधारण निकाय बैठक में उपस्थित और मतदान करने के हकदार सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा सोसाइटी के कम से कम तीन सदस्यों से गठित एक शासी निकाय निर्वाचित करेगी।

(2) शासी निकाय या इस प्रकार निर्वाचित इसके सदस्यों की अवधि ऐसी होगी जैसी विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, किन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु किसी सोसाइटी के शासी निकाय का कोई सदस्य पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, यदि उप-विधियाँ इस प्रकार की अनुमति दे :

परन्तु यह और कि शासी निकाय के सदस्य को इस प्रयोजन के लिए विशेषतया बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्यों के मतों के साधारण बहुमत द्वारा, ऐसे सदस्य को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, साधारण निकाय द्वारा हटाया जा सकेगा।

(3) प्रत्येक सोसाइटी व्यक्तियों के, जो शासी निकाय के सदस्य हैं, नाम, पते और व्यवसाय को दर्शाने वाला रजिस्टर रखेगी और अध्यक्ष या सचिव या शासी निकाय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्रार के पास निम्नलिखित दाखिल करेगा :-

- (i) रजिस्टर की एक प्रति, प्रथम शासी निकाय के सदस्यों के निर्वाचन की तारीख से चौदह दिन की अवधि के भीतर; और
- (ii) शासी निकाय के सदस्यों में प्रत्येक परिवर्तन का नोटिस ऐसे परिवर्तन की तारीख से चौदह दिन के भीतर।

(4) प्रत्येक सोसाइटी का प्रबन्धन उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचित शासी निकाय में निहित होगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो इस अधिनियम, नियमों और उप-विधियों द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएं।

निरर्हताएं।

16. कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा, यदि निर्वाचन की तारीख को,—

- (क) वह सोसाइटी को हानि कारित करने के लिए या सोसाइटी की सम्पत्ति का प्रतिधारण करने के लिए या किसी अन्य कारण से जो सोसाइटी

के हितों के लिए अहितकर है, न्यायालय या रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए निरहित है;

- (ख) विहित अभिदान फीस का बकाया उस पर है और ऐसे सदस्य को इस प्रभाव का नोटिस परिदत्त करने के पश्चात् पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त हो गई है; या
- (ग) उसे किसी संज्ञेय अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और तीन मास से अधिक अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया है; या
- (घ) वह निरहताओं, जैसी विहित की जाएं, में से किसी से ग्रस्त है ।

17. प्रत्येक सोसाइटी, अपनी उप-विधियों की एक प्रति, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को प्रवेश के समय, परिदत्त करेगी।

उप-विधियों की प्रतिलिपियों का प्रदाय।

18. प्रत्येक सोसाइटी अपने वार्षिक साधारण निकाय बैठक में संपरीक्षकों की रिपोर्ट सहित तुलनपत्र या लेखों की विवरणी की एक प्रति का प्रदाय प्रत्येक सदस्य को करेगी यदि अग्रिम में प्रदाय नहीं किया गया है।

तुलनपत्र आदि की प्रतिलिपियों का प्रदाय।

19. (1) सोसाइटी की उप-विधियां बारम्बारता (संख्या) और रीति विनिर्दिष्ट करेगी जिसमें शासी निकाय और साधारण निकाय की बैठकें होंगी, तथापि शासी निकाय तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगा और साधारण निकाय वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगा।

बैठकें ।

(2) प्रत्येक सोसाइटी कार्यवृत्त पुस्तक में साधारण निकाय की प्रत्येक बैठक और शासी निकाय की प्रत्येक बैठक की सभी कार्यवाहियों के भी कार्यवृत्त अभिलिखित करेगी।

(3) ऐसे कार्यवृत्त बैठक के लिए बुलाए गए समस्त सदस्यों को उक्त बैठक के तीस दिन के भीतर संसूचित किए जाएंगे।

20. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष में अपने सदस्यों की एक बार वार्षिक साधारण बैठक बुलाएगी जिसमें तुलन-पत्र की संपरीक्षित प्रति, आय और व्यय लेखे तथा संपरीक्षक की रिपोर्ट सहित सोसाइटी के प्रबन्धन की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

वार्षिक साधारण बैठक ।

(2) उप-धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सोसाइटी की साधारण बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार निम्नलिखित

प्रयोजनों के लिए बुलाई जाएगी :-

- (क) आगामी वर्ष के लिए शासी निकाय द्वारा तैयार सोसाइटी के क्रियाकलापों के प्रोग्राम (कार्यक्रम) के अनुमोदन के लिए ;
- (ख) नामनिर्दिष्ट सदस्यों से अन्यथा शासी निकाय के सदस्यों का विहित रीति में निर्वाचन, यदि कोई हो ;
- (ग) संपरीक्षा रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए; और
- (घ) किसी अन्य मामले पर विचार करना जो सोसाइटी के विनियमों के अनुसार समक्ष लाया जाए।

(3) ऐसी बैठक उप-धारा (1) के अधीन बुलाई गई अन्तिम पूर्ववर्ती बैठक की तारीख के पश्चात् पन्द्रह मास से अधिक समय के पश्चात् नहीं बुलाई जाएगी

(4) सोसाइटी द्वारा इसके रजिस्ट्रीकरण के पन्द्रह मास के भीतर प्रथम वार्षिक साधारण बैठक बुलाई जाएगी। सोसाइटी की पश्चात्पूर्वी वार्षिक साधारण बैठक प्रथम वार्षिक साधारण बैठक के पश्चात् बारह मास के भीतर बुलाई जाएगी :

परन्तु रजिस्ट्रार विशेष कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किए जाएंगे, उस समय, जिसके भीतर वार्षिक साधारण बैठक की जानी थी, का तीन मास से अनधिक और अवधि के लिए विस्तार कर सकेगा।

(5) साधारण बैठक की गणपूर्ति कुल सदस्यों के आधे या उप-विधियों में यथा-उपबंधित, जो भी अधिक हो, से होगी।

21. (1) विशेष साधारण बैठक अध्यक्ष द्वारा या शासी निकाय के सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा एक मास के भीतर किसी भी समय—

- (क) प्रस्तावित एजेंडे और ऐसी बैठक के लिए कारणों से अन्तर्विष्ट, सोसाइटी के सदस्यों के एक बटा पांच (1/5) या सदस्यों, जिनकी संख्या इस प्रयोजन के लिए उप-विधियों में विनिर्दिष्ट की हैं, जो भी निम्नतर हो, की लिखित अध्यक्षता पर, या

- (ख) रजिस्ट्रार के अनुरोध पर, बुलाई जाएगी।

(2) यदि सोसाइटी की विशेष साधारण बैठक उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अध्यक्षता के अनुसार नहीं बुलाई जाती है, तो रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी बैठक बुला सकेगा और वह बैठक शासी निकाय द्वारा सम्यक् रूप से बुलाई गई बैठक समझी जाएगी।

विशेष
साधारण
बैठक।

(3) रजिस्ट्रार को यह आदेश करने की शक्ति होगी कि उप-धारा (2) के अधीन बैठक को बुलाने में उपगत व्यय का संदाय सोसाइटी की निधियों में से या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो रजिस्ट्रार की राय में बैठक को बुलाने से इन्कार करने या बुलाने में असफल रहने के लिए जिम्मेदार था या थे, किया जाएगा।

(4) विशेष साधारण बैठक के लिए गणपूर्ति वैसी ही होगी जैसी धारा 19 की उप-धारा (5) में वार्षिक साधारण बैठक के लिए उपबंधित है।

22. (1) शासी निकाय या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का इसकी उप-विधियों द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की किसी भी सम्पत्ति, अधिकार या दावे की बाबत या से सम्बन्धित कोई कार्रवाई या अन्य विधिक कार्यवाही ला सकेगा या लगवा सकेगा या प्रतिवाद कर सकेगा या परिवाद करवा सकेगा और ऐसी किसी सम्पत्ति, अधिकार या दावे की बाबत वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) किसी भी कार्रवाई या विधिक कार्यवाहियों का, सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य की मृत्यु, पद से त्याग-पत्र या हटाए जाने से उपशमन नहीं होगा या वे बन्द नहीं की जाएंगी।

23. (1) संगम ज्ञापन के अभिदाता सोसाइटी के प्रथम सदस्य होंगे।

सदस्यों का रजिस्टर।

(2) प्रत्येक सोसाइटी अपने मुख्य कार्यालय में, अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियां प्रविष्टि करेगी, अर्थात् :-

- (क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता और तारीख सहित हस्ताक्षर;
- (ख) तारीख जिसको सदस्यों ने प्रवेश दिया हो; और
- (ग) तारीख जिसको सदस्यों का सदस्य न रह जाना।

(3) सदस्यों का रजिस्टर सोसाइटी की सदस्यता और उसमें प्रविष्टि सभी विषयों (मामलों) का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य होगा :

परन्तु कोई भी सदस्य, जिसका अभिदान तत्समय छह मास से अधिक अवधि से बकाया है, इस अधिनियम के अधीन सोसाइटी की किन्हीं कार्यवाहियों में मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) यदि सदस्यों के रजिस्टर में सदस्यों के प्रवेश की या सदस्यता के न रहने की प्रविष्टियों के तीस दिन के भीतर नहीं की जाती है, तो व्यतिक्रमी प्रत्येक पदाधिकारी जुर्माने से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(5) साधारण निकाय के अनुमोदन के अध्याधीन सदस्य को शासी निकाय द्वारा निष्कासित किया जा सकेगा, यदि वह सोसाइटी के हित के प्रतिकूल कार्य करता है।

सदस्यों का अपने खिलाफ अन्य पक्षकारों के रूप में वाद लाए जाने के दायित्वाधीन होना।

24 (1) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी सदस्य पर, जिसकी तरफ कोई अभिदान (चन्दा) बकाया हो, जिसे वह सोसाइटी के विनियमों के अनुसार संदत्त करने को आबद्ध है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति पर स्वयं कब्जा या उसका निरोध इस रीति से या इतने समय तक कर लेता है जो ऐसे विनियमों के प्रतिकूल है, या जो सोसाइटी की किसी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या नष्ट करता है, ऐसे बकाया के लिए या सम्पत्ति के ऐसे कब्जे, निरोध, क्षति या नाश से प्रोदभूत होने वाले नुकसान के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, वाद लाया जा सकेगा।

(2) सोसाइटी की प्रेरणा पर उप-धारा (1) के अधीन लाए गए किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों में यदि प्रतिवादी सफल होता है और उसके पक्ष में उसके खर्चों की वसूली का अधिनिर्णय दिया जाता है, तो वह उस अधिकारी से, जिसके नाम से वाद या अन्य विधिक कार्यवाही लाई गई थी, या सोसाइटी से उन्हें वसूल करने का चयन कर सकेगा और पश्चात्पूर्ती दशा में वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त सोसाइटी की सम्पत्ति के खिलाफ आदेशिका प्राप्त करेगा।

अपराधों के दोषी सदस्यों का अन्य पक्षकारों के रूप में दण्डनीय होना।

25. रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कोई सदस्य जो उस सोसाइटी के किसी धन या अन्य सम्पत्ति को चुराएगा, हड़पेगा या उसका गबन करेगा अथवा किसी सम्पत्ति को जानबूझकर और विद्वेषतः नष्ट करेगा या क्षति पहुंचाएगा अथवा किसी विलेख, बन्धपत्र, धन के लिए प्रतिभूति, रसीद या अन्य लिखत को कुटरचित करेगा जिससे सोसाइटी की निधियां हानि की जोखिम में पड़ जाएं, वैसे ही अभियोजनीय होगा और यदि सिद्धदोष हुआ तो वैसी ही रीति में दण्डनीय होगा जैसे कोई व्यक्ति जो ऐसा सदस्य न हो, वैसे ही अपराध की बाबत अभियोजनीय और दण्डनीय होता।

उप-विधियों के अधीन प्रोदभूत होने वाली शास्ति की वसूली।

26. जब कभी सोसाइटी के विनियमों के अनुसार सम्यक् रूप से बनाई गई किसी उप-विधि द्वारा सोसाइटी के किसी विनियम या उप-विधि के भंग के लिए कोई धनीय शास्ति अधिरोपित की गई है तो ऐसी शास्ति जब प्रोदभूत होती है, अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय में, जहां प्रतिवादी निवास करता है या जहां सोसाइटी का कार्यालय स्थित है, जैसे उसका शासी निकाय समीचीन समझे, वसूल किया जा सकेगा।

अध्याय-5

सोसाइटियों की सम्पत्तियां और निधियां

27. इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की स्थावर और जंगम सम्पत्ति ऐसी सोसाइटी के साधारण निकाय में निहित समझी जाएगी और सभी सिविल और दाण्डिक कार्यवाहियों में ऐसी सोसाइटी के साधारण निकाय की, उनके उचित अभिनाम (हक) से, सम्पत्ति के रूप में वर्णित की जा सकेगी।

सोसाइटी की सम्पत्ति कैसे निहित होगी।

28. सोसाइटी द्वारा किसी भी सम्पत्ति का विक्रय, दान या अन्यथा अर्जन या अन्तरण इसके साधारण निकाय के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा :
परन्तु सम्पत्ति के ऐसे समस्त संव्यवहारों से सम्बन्धित सूचना पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर रजिस्ट्रार को भी दी जाएगी और अभिलिखित करवाई जाएगी।

सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बन्धन।

29. प्रत्येक सोसाइटी, यथास्थिति, प्रधान, अध्यक्ष या सचिव अथवा शासी निकाय के नाम पर, जैसा कि सोसाइटी के विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए, और ऐसे अवधारण के अभाव में ऐसे व्यक्ति के नाम पर, जो उस अवसर के लिए शासी निकाय द्वारा नियुक्त किया जाए, वाद ला सकेगी और उस पर वाद लाया जा सकेगा:

सोसाइटियों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद।

परन्तु किसी व्यक्ति के लिए, जिसका सोसाइटी के विरुद्ध कोई दावा या मांग हो, यह सक्षम होगा कि वह उसके प्रधान या अध्यक्ष या सचिव अथवा शासी निकाय पर वाद ला सके, यदि शासी निकाय को आवेदन करने पर किसी अन्य अधिकारी या व्यक्ति को प्रतिवादी होने के लिए नामनिर्देशित नहीं किया जाता।

30. किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या कार्यवाही का इस कारण उपशमन नहीं होगा या वह बन्द नहीं होगी कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा या जिसके विरुद्ध ऐसा वाद या कार्यवाही लाई गई या जारी रखी गई थी, मर गया है या उस हैसियत में कायम नहीं रह गया है, जिसके नाम से वह वाद लाया था या उस पर वाद लाया गया था, किन्तु वही वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्ति के उत्तराधिकारी के नाम में या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेगी।

वादों का उपशमन न होना।

31. (1) यदि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य के विरुद्ध कोई निर्णय पारित किया जाता है तो ऐसा निर्णय ऐसे व्यक्ति या अधिकारी की स्थावर या जंगम सम्पत्ति के विरुद्ध या वैयक्तिक रूप से उसके विरुद्ध प्रवृत्त नहीं किया जाएगा किन्तु रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवृत्त किया जाएगा।

सोसाइटी के विरुद्ध निर्णय का प्रवर्तन।

(2) निष्पादन के लिए आवेदन में निर्णय और उस पक्षकार के, जिसके विरुद्ध उसे पारित किया गया हो, केवल रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से, यथास्थिति, वाद लाने या उसके विरुद्ध वाद लाए जाने की बात उपवर्णित होगी और यह अपेक्षा की जाएगी कि निर्णय को रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की सम्पत्ति के विरुद्ध प्रवर्तित कराया जाए।

सोसाइटी
द्वारा लेखा जिनमें—
पुस्तकों का
रखा जाना।

32. (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने मुख्य कार्यालय में उचित लेखा पुस्तकें रखेगी

- (क) अभिप्राप्त समस्त धन राशियों और उनके स्रोत तथा सोसाइटी द्वारा व्यय की गई समस्त धनराशियों तथा उन उद्देश्यों या प्रयोजनों, जिनके लिए ऐसी राशियां व्यय की गई हैं;
- (ख) सोसाइटी की परिसम्पत्तियों और दायित्वों; और
- (ग) सोसाइटी द्वारा अर्जित जंगम सम्पत्ति के ब्यौरों की सही रूप प्रविष्टि की जाएगी।

(2) लेखा पुस्तकें, पदाधिकारी या सोसाइटी के सदस्यों या रजिस्ट्रार अथवा कार्यालय समय के दौरान रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएंगी।

(3) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए इसमें विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत उचित लेखा पुस्तकें रखी हुई नहीं समझी जाएगी यदि वे सोसाइटी के कार्यकलापों की स्थिति की सही और स्वच्छ स्थिति नहीं दर्शाती हैं और इसके संव्यवहारों को स्पष्ट नहीं करती है।

रजिस्ट्रार
की
अभिलेख,
आदि का
अभिग्रहण
करने की
शक्तियां।

33. (1) जहां रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि—

- (क) सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्टर या लेखा बहियों से अन्तःक्षेप (छेड़छाड़) करने या उन्हें नष्ट करने की संभावना है और सोसाइटी की निधियों तथा सम्पत्ति के दुरुपयोजन या दुर्विनियोजन की संभावना है; या
- (ख) यदि सोसाइटी के शासी निकाय का सोसाइटी की साधारण बैठक में पुनः गठन किया जाता है और शासी निकाय के पद छोड़ने वाले सदस्य, सोसाइटी के अभिलेख तथा सम्पत्ति के अधिभार को इसे रखने वाले या ऐसा अधिभार अभिप्राप्त करने के हकदार को अधिभार देने से इन्कार कर देते हैं,

तो रजिस्ट्रार उस द्वारा सम्यक् रूप से लिखित में प्राधिकृत व्यक्ति को निदेश देते हुए सोसाइटी की ऐसी बहियों और अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करने और कब्जा लेने का आदेश देगा और ऐसी बहियों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए दायी सोसाइटी का अधिकारी या के अधिकारी इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति को उनका परिदान करेगा या करेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा और पुलिस बल सहित ऐसे न्यूनतम बल का प्रयोग करेगा या करवाएगा जैसा आवश्यक समझा जाए।

अध्याय-6

वार्षिक विवरणियां, लेखा परीक्षा, और पर्यवेक्षण

34. प्रत्येक वर्ष में एक बार, उस दिन के, जिसको कि सोसाइटी के विनियमों के अनुसार सोसाइटी की वार्षिक साधारण बैठक की गई है, उत्तरवर्ती चौदहवें दिन को या उससे पूर्व, या यदि विनियमों में वार्षिक साधारण बैठक के लिए उपबन्ध नहीं है तो जनवरी के इकतीसवें दिन के चौदह दिनों के भीतर शासी निकाय के हस्ताक्षरों सहित पूर्ण नामों, स्थायी पतों और मुख्य उपजीविकाओं और अन्य, यदि कोई हो से अन्तर्विष्ट सूची अध्यक्ष या सचिव द्वारा ऐसे दस्तावेजों के साथ ऐसे प्ररूप में ऐसी फीस सहित जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जाएगी :

शासी
निकाय की
वार्षिक सूची
का दाखिल
किया
जाना।

परन्तु रजिस्ट्रार लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अनुपालना के लिए पन्द्रह दिन से अनधिक और समय देगा :

परन्तु यह और कि यदि कोई सोसाइटी विनिर्दिष्ट समय सीमा या बढ़ाए गए समय के भीतर सूची दाखिल करने में असफल रहती है तो वह इसे ऐसी और बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो तीस दिन से अधिक की न हो और ऐसी विलम्ब फीस सहित, जैसी विहित की जाए, इसे दाखिल कर सकेगा।

35. (1) प्रत्येक सोसाइटी रजिस्ट्रार को, सोसाइटी के वार्षिक साधारण बैठक की तारीख से नब्बे दिन के भीतर या जहां विनियम वार्षिक साधारण बैठक के लिए उपबन्ध नहीं करते, वहां प्रत्येक वर्ष अप्रैल के तीसवें दिन से, इसके लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से संपरीक्षित पूर्ण ब्यौरे सहित आय व्यय का विवरण, लेखा परीक्षा रिपोर्ट आदि समस्त वित्तीय क्रियाकलापों के ब्यौरे सहित पूर्व वर्ष का तुलनपत्र ऐसी फीस के साथ, जैसी विहित की जाए, रजिस्ट्रार को भेजेगा। यदि सोसाइटी नियत समय के भीतर उपर्युक्त विवरणों को भेजने में असफल रहती है तो सोसाइटी ऐसी विलम्ब फीस, जैसी विहित की जाए, का संदाय करने के लिए दायी होगी।

लेखापरीक्षा।

(2) ऐसे विवरण (विवरणी) की प्राप्ति पर, रजिस्ट्रार विवरणों (विवरणियों) को सत्यापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सोसाइटियों के रजिस्टर, बहियां और अन्य अभिलेख विहित रीति में बनाए गए हैं और निधियां सोसाइटी और इसके उद्देश्यों के संवर्धन के लिए उपयोजित की गई हैं और वह निधियों के उपयोजन की बाबत ऐसे अनुदेश भी जारी कर सकेगा जैसे वह उचित समझे :

परन्तु एक लाख रुपये से अधिक वार्षिक संव्यवहार रखने वाली ऐसी सोसाइटी के, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक रूप से संपरीक्षित, लेखे रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किए जाएंगे:

परन्तु यह और कि पांच लाख रुपये से अधिक संव्यवहार रखने वाली सोसाइटी किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में प्रत्येक वर्ष लाभ/हानि लेखा विवरणी सहित अपना संपरीक्षित तुलन-पत्र प्रकाशित करवाएगी।

(3) यदि रजिस्ट्रार विशेष लेखा परीक्षा का जिम्मा लेना आवश्यक समझता है तो वह किसी भी सोसाइटी के लेखों की लेखा परीक्षा कर सकेगा या उस द्वारा इस निमित्त लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें संपरीक्षित करवा सकेगा।

(4) रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सभी समयों पर सोसाइटी की समस्त लेखा बहियों और अन्य कागजात देख सकेगा और सोसाइटी का प्रत्येक अधिकारी, सोसाइटी के लेखों और कार्यप्रणाली से सम्बन्धित ऐसी सूचना जैसी ऐसे निरीक्षण करने वाला व्यक्ति अपेक्षा करे, उसे देगा।

दस्तावेजों
का
निरीक्षण।

36. कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए सभी या उनमें से किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा, या ऐसी फीस जैसी विहित की जाए के साथ आवेदन देकर रजिस्ट्रार द्वारा अनुप्रमाणित किए जाने वाले किसी ऐसे दस्तावेज की प्रति या उद्धरण की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी अनुप्रमाणित प्रति उसमें अन्तर्विष्ट विषयों का, सभी विधिक कार्यवाहियों में, जो कोई भी हो, प्रथमदृष्टया साक्ष्य होगी।

हाजिर
कराने, आदि
की शक्ति।

37. रजिस्ट्रार को, उन्हीं साधनों द्वारा और जहां तक संभव हो सके उसी रीति में जो सिविल न्यायालय की दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा उपबंधित है, साक्षियों को, जिनके अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकार भी आते हैं, या उनमें से किसी को समन करने, उनको हाजिर कराने और उन्हें साक्ष्य देने के लिए बाध्य करने तथा दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने की शक्ति होगी।

रजिस्ट्रार
की
जानकारी
मांगने की
शक्ति।

38. (1) जहां रजिस्ट्रार की, किसी दस्तावेज, जिसे सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, के परिशीलन पर, यह राय है कि कोई जानकारी या स्पष्टीकरण इसलिए आवश्यक है ताकि ऐसा दस्तावेज उन विषयों जिन से यह सम्बन्धित है की, पूर्ण विशिष्टियां दे सके, तो वह लिखित आदेश द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने वाली सोसाइटी से, ऐसे समय के भीतर जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित में ऐसी जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन सोसाइटी द्वारा आदेश की प्राप्ति पर, सोसाइटी और उन सभी व्यक्तियों का, जो सोसाइटी के अधिकारी हैं, उनकी श्रेष्ठतम शक्ति के अनुसार ऐसी सूचना या स्पष्टीकरण देना कर्तव्य होगा।

अध्याय-7

जांच और विवाद का निपटारा

39. (1) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से या उप-धारा (2) के अधीन किए गए आवेदन रजिस्ट्रार पर, स्वयं या उसके द्वारा लिखित में ओदश द्वारा, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सोसाइटी के गठन, द्वारा जांच। कार्यकरण और वित्तीय स्थिति की जांच कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई जांच—

- (क) सोसाइटी के शासी निकाय के सदस्यों के बहुमत के; या
- (ख) सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई के, शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर की जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार या उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, इस धारा के अधीन जांच के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

- (क) उसे सोसाइटी से सम्बन्धित या उसकी अभिरक्षा में रखी बहियों, लेखों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों की सभी समयों पर अबाध पहुँच होगी और वह किसी व्यक्ति को, जिसके कब्जे में, या जो ऐसी किन्हीं बहियों, लेखों दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी या अन्य सम्पत्तियों की अभिरक्षा का दायी है, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए, यदि वे सोसाइटी के मुख्यालय से सम्बन्धित हैं तो उसके मुख्यालय के किसी भी स्थान पर और यदि वे सोसाइटी की किसी शाखा से सम्बन्धित हैं तो शहर के किसी भी स्थान पर जहां पर ऐसी शाखा स्थित है या अपने कार्यालय में, बुला सकेगा ;
- (ख) वह किसी व्यक्ति को, जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसे सोसाइटी के किसी भी क्रियाकलाप की जानकारी है, अपने समक्ष, सोसाइटी के मुख्यालय के किसी स्थान या उसकी किसी

शाखा या अपने कार्यालय में पेश होने के लिए बुला सकेगा और ऐसे व्यक्ति का शपथ पर परीक्षण कर सकेगा; और

- (ग) वह, सोसाइटी के साधारण निकाय बैठक हेतु, नोटिस की अवधि विनिर्दिष्ट करने वाले, किसी विनियम या उप-विधि के होते हुए भी, सोसाइटी के अधिकारियों से, ऐसे समय पर सोसाइटी के मुख्यालय पर या सोसाइटी के मुख्यालय के किसी अन्य स्थान पर, सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक, ऐसे मामलों का निर्धारण करने के लिए जैसे उस द्वारा निदिष्ट किए जाएं, बुलाने की अपेक्षा कर सकेगा और जहां पर सोसाइटी के अधिकारी ऐसी कोई बैठक बुलाने, से इन्कार करते हैं या बुलाने में असफल रहते हैं, तो उसको स्वयं बैठक बुलाने की शक्ति होगी; और
- (घ) खण्ड (ग) के अधीन बुलाई गई सोसाइटी की किसी भी बैठक को, सोसाइटी के विनियमों या उप-विधियों के अधीन बुलाई गई साधारण निकाय की बैठक की, समस्त शक्तियां होंगी और इसकी कार्यवाहियां ऐसी उप-विधियों द्वारा विनियमित की जाएंगी।

(4) जब इस धारा के अधीन कोई जांच की जाती है, तो रजिस्ट्रार, जांच के परिणामों को सोसाइटी को संसूचित करेगा और सोसाइटी को समुचित निदेश जारी कर सकेगा, जो कि सम्बन्धित समस्त पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

अधिभार।

40. (1) जहां धारा 35 के अधीन लेखा परीक्षा या धारा 39 के अधीन किसी जांच के दौरान, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति जिसने सोसाइटी की स्थापना या प्रबन्धन में भाग लिया हो या सोसाइटी के किसी भूतपूर्व या वर्तमान अध्यक्ष, सचिव, सदस्य या कर्मचारिवृन्द ने सोसाइटी के किसी धन या सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया है या प्रतिधारित किया है या उसका दायी या देनदार बन गया है या सोसाइटी के सम्बन्ध में अपकरण या न्यास भंग का दोषी रहा है, तो रजिस्ट्रार, अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर या सोसाइटी के शासी निकाय से प्राप्त आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, ऐसे व्यक्ति के आचरण का परीक्षण कर सकेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उससे क्रमशः धन या सम्पत्ति या उसके किसी भाग का, ब्याज सहित, ऐसी दर पर जैसी विहित की जाए, प्रतिसंदाय करने या प्रत्यावर्तित करने या दुरुपयोजन, रिटेनर, अपकरण या न्यास भंग, की बाबत प्रतिकर के रूप में सोसाइटी की परिसम्पत्तियों में ऐसी राशि का अभिदाय करने, जैसा रजिस्ट्रार उचित समझे, के आदेश करेगा।

(2) इस धारा के अधीन सोसाइटी को प्रतिसंदत्त किए जाने के लिए आदिष्ट या इसकी परिसम्पत्तियों के अभिदाय के रूप में वसूल की गई कोई राशि, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त की गई अध्यपेक्षा पर हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(3) यह धारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, किसी दाण्डिक अभियोजन आरम्भ करने या आरम्भ किए जाने के प्रस्ताव के होते हुए भी लागू होगी।

41. (1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी सोसाइटी शासी निकाय या लोक सेवा जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि प्रदान करने में लगी किसी अन्य को अतिष्ठित सोसाइटी का शासी निकाय,—

- (क) इस अधिनियम या सोसाइटी के विनियमनों या उप-विधियों के अधीन या द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों या राज्य सरकार या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी विधिपूर्ण आदेश की अनुपालना में बार-बार व्यतिक्रम करता है या उपेक्षावान रहता है, या ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करने में अनिच्छुक है; या
- (ख) सोसाइटी या इसके सदस्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करता है; या
- (ग) अन्यथा उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा हो;

तो रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा शासी निकाय को हटा सकेगा और प्रथमतः छः मास से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, सोसाइटी के क्रियाकलापों का प्रबन्ध करने के लिए एक या एक से अधिक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु जहां सोसाइटी के शासी निकाय को, अनन्यतः इस आधार पर, कि शासी निकाय का निर्वाचन इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार नहीं करवाए गए हैं, हटाए जाने का प्रस्ताव है, तो इस उप-धारा के अधीन तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए विनियमों या उप-विधियों के उपबन्धों के अनुसार उसका निर्वाचन करवाने हेतु शासी निकाय की बैठक न बुलाई हो, किन्तु नए शासी निकाय निर्वाचित कराने में असफल रहा हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि शासी निकाय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(3) उप-धारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि को, रजिस्ट्रार द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए छः मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा और तत्पश्चात् अवधि को और नहीं बढ़ाया जाएगा।

(4) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक (प्रशासकों) को रजिस्ट्रार के नियन्त्रण और ऐसे निदेशों, जैसे वह समय-समय पर दे, के अधीन रहते हुए शासी निकाय या सोसाइटी के किन्हीं अधिकारियों के समस्त या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग करने और समस्त ऐसी कार्यवाई करने जो सोसाइटी के हित में करनी अपेक्षित हो, की शक्ति होगी :

परन्तु प्रशासक किसी नए सदस्य की प्रविष्टि नहीं करेगा/करेंगे और न ही कोई नियुक्ति करेगा/करेंगे।

(5) रजिस्ट्रार प्रशासक (प्रशासकों) को संदेय पारिश्रमिक को नियत कर सकेगा, और ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा सोसाइटी के प्रबन्ध में उपगत अन्य खर्च, यदि कोई है, सोसाइटी की निधियों से संदेय होंगे।

(6) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक नियुक्ति की अवधि के अवसान पर, सोसाइटी के विनियमों के अनुसार नए शासी निकाय के गठन की व्यवस्था करेगा/करेंगे।

(7) यदि सोसाइटी के साधारण निकाय और उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक (प्रशासकों) के मध्य, किसी मामले की बाबत यदि कोई मतभेद होता है, तो इसको विनिश्चय हेतु रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(8) नोटिस जारी करने और शासी निकाय को हटाए जाने का आदेश पारित करने के मध्य की अवधि के दौरान, रजिस्ट्रार शासी निकाय से ऐसे प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन और अनुमोदन से कार्य करने की अपेक्षा कर सकेगा जिसे रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और किया गया कोई आदेश या पारित संकल्प या शासी निकाय द्वारा किया गया अन्य कोई कार्य, तब प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया गया हो।

(9) जहां रजिस्ट्रार की, उप-धारा (1) के अधीन कार्यवाई करने के लिए अग्रसर होते समय यह राय है कि कार्यवाहियों की अवधि के दौरान शासी निकाय या किसी सदस्य का निलम्बन, सोसाइटी के हित में, आवश्यक है तो वह, यथास्थिति, ऐसे शासी निकाय या सदस्य को निलंबित कर सकेगा और जहां शासी निकाय को निलम्बित कर

दिया गया है, वहां कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक, सोसाइटी के क्रियाकलापों के उचित प्रबन्ध हेतु ऐसे प्रबन्ध करेगा, जैसे वह उचित समझे :

परन्तु ऐसे निलंबित शासी निकाय या सदस्य को हटाया नहीं गया है, तो यह या वह यथापूर्वक रहेंगे और निलंबन की अवधि की इसकी या उसकी अवधि में गणना की जाएगी।

42. (1) सोसाइटी के क्रियाकलापों से सम्बन्धित किसी मामले की बाबत शासी प्रबन्धन के निकाय या सोसाइटी के सदस्यों या इसके कर्मचारियों के मध्य किसी विवाद के उत्पन्न होने की दशा में, सोसाइटी का कोई सदस्य या शासी निकाय या कर्मचारी या भूतपूर्व कर्मचारी या भूतपूर्व सदस्य, विवाद को, रजिस्ट्रार के विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट कर सकेगा, जो या तो विवाद का स्वयं विनिश्चय करेगा या ऐसे विवाद को किसी अन्य अधिकारी को निपटारे के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(2) उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु विवाद में, सोसाइटी द्वारा या के विरुद्ध दावे से सम्बन्धित मामले और शासी निकाय के निर्वाचन से उत्पन्न कोई मामला भी सम्मिलित होगा।

अध्याय-8

सोसाइटियों का समामेलन, विभाजन, विघटन और परिसमापन

43. (1) रजिस्ट्रार को सूचित कर, कोई दो या दो से अधिक सोसाइटियां, दोनों या समस्त ऐसी सोसाइटियों के विशेष संकल्प द्वारा और प्रथम बैठक के पश्चात् एक मास के अन्तराल के पश्चात् बुलाई गई दोनों या समस्त ऐसी सोसाइटियों की द्वितीय बैठक में वैसे ही संकल्प द्वारा पुष्टि पर, एक सोसाइटी में, विघटन के साथ या बिना किसी विघटन के या निधियों के विभाजन के साथ या के बिना समामेलित हो सकेगी।

(2) कोई सोसाइटी विशेष संकल्प द्वारा स्वयं को दो या दो से अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर सकेगी, और ऐसे संकल्प में सोसाइटी की परिसम्पत्तियों और दायित्वों को नई सोसाइटियों के बीच, जिसमें यह स्वयं को विभक्त करने का प्रस्ताव करती है, विभाजन हेतु प्रस्ताव अन्तर्विष्ट होंगे और कार्यान्वयन का क्षेत्र तथा सदस्यों, जिनके द्वारा प्रत्येक नई सोसाइटी गठित होगी, भी विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) इस धारा के अनुसरण में कोई समामेलन या विभाजन किसी सोसाइटी, जो ऐसे समामेलन या विभाजन का पक्षकार थी, के लेनदार के किसी अधिकार के प्रतिकूल नहीं होगा।

सोसाइटी का
विघटन और
इसके
कार्यकलापों
का
समायोजन।

44. (1) सोसाइटी विशेष संकल्प द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि यह विघटित कर दी जाएगी और तदुपरि, रजिस्ट्रार को पूर्व संसूचना सहित, यह संकल्प में विनिर्दिष्ट समय पर विघटित कर दी जाएगी तथा सोसाइटी की उप-विधियों, यदि कोई हो, के अनुसार सोसाइटी की सम्पत्ति तथा इसके दावों और दायित्वों के निपटारे और परिनिर्धारण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, और यदि इस प्रभाव की कोई उप-विधियां नहीं हैं, तो यह ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसा साधारण निकाय समीचीन समझे :

परन्तु शासी निकाय के सदस्यों या सोसाइटी के सदस्यों के बीच उत्पन्न किसी विवाद की दशा में, इसके क्रियाकलापों का समायोजन न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और न्यायालय समापक की नियुक्ति सहित मामले में ऐसा आदेश करेगा जैसा यह उचित समझे :

परन्तु यह और कि यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का सदस्य या अभिदाता है, तो ऐसी सोसाइटी सम्बन्धित सरकार की सहमति के बिना विघटित नहीं की जाएगी।

(2) इस धारा के अधीन विघटित सोसाइटी, रजिस्ट्रार के पास, पूर्ण रिपोर्ट, यह दर्शाते हुए कि सम्पत्ति का व्ययन (निपटारा) किस प्रकार किया गया है, दाखिल करेगी।

रजिस्ट्रार की
कतिपय
परिस्थितियों
में
रजिस्ट्रीकरण
रद्द करने
की शक्ति।

45. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार लिखित आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को, निम्नलिखित किन्हीं आधारों पर रद्द कर सकेगा :-

- (क) यह कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ने इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है; या
- (ख) यह कि रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी दिवालिया है या अवश्यम्भावी ऐसी बन जाएगी; या
- (ग) यह कि ऐसी किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का कारबार कपटपूर्वक किया जा रहा है या उप-विधियों या धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए ज्ञापन में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार नहीं है।

(2) यदि रजिस्ट्रार को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी कोई विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कर रही है या सोसाइटी के नियन्त्रणाधीन किसी परिसर के

भीतर विधिविरुद्ध क्रियाकलाप करना अनुज्ञात कर रही है, तो रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी के क्रियाकलापों की जांच कर सकेगा और प्रत्येक ऐसी जांच की बाबत, रजिस्ट्रार को वही शक्तियां होंगी जैसी कि धारा 39 की उप-धारा (3) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

(3) यदि उप-धारा (2) के अधीन जांच पर, रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि ऐसे कोई सोसाइटी कोई विधिविरुद्ध क्रियाकलाप कर रही है या सोसाइटी के नियन्त्रणाधीन किसी परिसर के भीतर किसी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप कार्यान्वित करना अनुज्ञात किया है, तो वह, सोसाइटी को युक्तियुक्त कारण बताओ नोटिस, कि क्यों न सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया जाए, देने के पश्चात् और सोसाइटी की ओर से किए गए अभ्यावेदनों, यदि कोई है, पर विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करेगा और रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी को रद्दकरण का आदेश तत्काल, संसूचित करेगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई क्रियाकलाप विधिविरुद्ध समझा जाएगा यदि ऐसा क्रियाकलाप तत्समय प्रवृत्त विधि के किन्हीं उपबन्धों के अधीन दण्डनीय अपराध है।

46. यदि किसी सोसाइटी के विघटन पर, उसके समस्त ऋणों और दायित्वों की तुष्टि हो जाने के पश्चात्, कोई भी सम्पत्ति, चाहे किसी प्रकार की हो, रह जाए तो वह उक्त सोसाइटी के सदस्यों या उनमें से किसी को संदत्त या उनमें वितरित नहीं की जाएगी किन्तु किसी ऐसी अन्य सोसाइटी को दी जाएगी जो, विघटन के समय पर स्वयम् उपस्थित सदस्यों के तीन बटा पांच के अन्यून मत द्वारा या उसके अभाव में धारा 44 में विनिर्दिष्ट न्यायालय द्वारा, अवधारित की जाए।

47. धारा 44 के अधीन किए गए आदेश, लागू होने पर, निम्न प्रकार से प्रवर्तित होंगे :—

- (क) जब समापक द्वारा किए गए हों तो स्थानीय अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा, उसी रीति में ऐसे न्यायालय की डिक्री के रूप में; और
- (ख) जब न्यायालय द्वारा अपील पर किए गए हों, उसी रीति में उस न्यायालय की डिक्री के रूप में।

48. (1) धारा 44 के अधीन विघटित किसी सोसाइटी के सदस्यों के लिए, ऐसी सोसाइटी के विघटन के समय पर उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा यह अवधारित करना विधिपूर्वक होगा कि इसके समस्त ऋणों और दायित्वों की तुष्टि हो जाने के पश्चात् कोई भी सम्पत्ति, चाहे किसी प्रकार की हो, जो शेष बची हो, सरकार को धारा 1 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के उपयोग हेतु दी जाएगी।

विघटन पर किसी सदस्य का लाभ प्राप्त न करना।

आदेश का प्रवर्तन।

विघटन के पश्चात् अवधारित करना कि सम्पत्ति का सरकार द्वारा उपयोग किया जाए।

(2) धारा 44 के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की दशा में सोसाइटी की समस्त जंगम और स्थावर परिसम्पत्तियां या इसके संस्थान या केन्द्र, सहायता अनुदान, सहायिकी या दान जो सोसाइटी ने केन्द्र या राज्य सरकार या किसी वैधानिक निकाय से प्राप्त किए हैं कि सीमा तक, राज्य सरकार में, निहित होंगे और जिला सम्पत्ति जहां स्थित है, के कलक्टर का यह कर्तव्य होगा कि इसका प्रभार, रजिस्ट्रार द्वारा रद्दकरण की सूचना देने पर, ले।

अध्याय-9

अपराध और शास्तियां

शास्ति।

49. यदि कोई सोसाइटी या सोसाइटी के कार्यकलापों के प्रबन्धन से न्यस्त धारा 35 और 38 में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति जिससे कोई जानकारी या विवरणी देना अपेक्षित है—

- (i) ऐसी जानकारी या विवरणी जिसे इसके मिथ्या होने का ज्ञान है से जानबूझकर देने से इन्कार करता है या विधिपूर्ण प्रतिहेतु के बिना प्रस्तुत करने में उपेक्षा करता है; या
- (ii) किसी सूचना या विवरणी जिसे इसके मिथ्या होने का ज्ञान है को जानबूझकर देता है या दिलवाता है; या
- (iii) सुसंगत धारा के अधीन दी जाने को अपेक्षित किसी सूचना को अभिप्राप्त करने हेतु किसी आवश्यक प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करता है या जानबूझकर मिथ्या उत्तर देता है,

तो दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए दो हजार रूपए तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा।

अपराधों का
संज्ञान।

50. (1) प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान रजिस्ट्रार या उस द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय न करेगा।

अध्याय-10

अपील

51. (1) अपील निम्नलिखित को होगी.-

अपील।

(क) यदि आदेश, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार द्वारा मूल मामले में या खण्ड (ख) के अधीन अपील में किया गया है तो राज्य सरकार को;

(ख) यदि आदेश धारा 3 की उप-धारा (2) के अधीन नियुक्त अधीनस्थ अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया है तो धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार को।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील, आदेश की संसूचना की तारीख से साठ दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, ऐसी फीस के साथ जैसी विहित की जाए, की जाएगी:

परन्तु अपील प्राधिकारी, किसी अपील को साठ दिन की उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उस के पास इस अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

अध्याय-11

प्रकीर्ण

52. इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाला या प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना।

53. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ अथवा उसके प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होंगी।

क्षतिपूर्ति।

54. (1) कोई भी सोसाइटी जो राज्य से बाहर रजिस्ट्रीकृत है; परन्तु अपनी शाखा (शाखाएं) राज्य में खोलना चाहती हैं तो ऐसी शाखा खोलने से पूर्व वह रजिस्ट्रार से

रजिस्ट्रार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करेगी तथा ऐसी फीस का संदाय करेगी, जो विहित की जाए; परन्तु यदि ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रार या सरकार के निदेश या आदेश का अनुपालन नहीं करती है तो अनापत्ति प्रमाण—पत्र रद्द कर दिया जाएगा।

(2) ऐसी सोसाइटी की शाखा (शाखाएं) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शासित की जाएंगी।

फीस। 55. (1) राज्य सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रभार्य फीस विहित कर सकेगी, अर्थात्:—

- (क) सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए ;
- (ख) रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए ;
- (ग) रजिस्ट्रीकरण से पूर्व या पश्चात् आदेशों, विनिश्चयों, प्रविष्टियों या दस्तावेजों की प्रतियां बनाने या प्रदान करने के लिए ; और
- (घ) ऐसे अन्य मामलों के लिए जो सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं।

(2) इस अधिनियम के अनुसरण में रजिस्ट्रार या सरकार के किसी अन्य अधिकारी को संदत्त समस्त फीस, प्रभार और अन्य राशियां राज्य की संचित निधि में जमा की जाएंगी।

नियम बनाने की शक्ति। 56. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:—

- (क) धारा 6 के अधीन रजिस्ट्रीकरण फीस का उद्ग्रहण ;
- (ख) रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ज्ञापन या विनियमों या उप-विधियों के संशोधन हेतु प्ररूप और अनुसरण में लाई जाने वाली प्रक्रिया तथा धारा 9 के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस;

- (ग) सोसाइटी के नाम में परिवर्तन करने हेतु प्रक्रिया और शर्तें तथा धारा 11 के अधीन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (घ) धारा 16 के अधीन सोसाइटी के शासी निकाय की सदस्यता हेतु अर्हताएं या निरर्हताएं;
- (ङ) धारा 20 के अधीन शासी निकाय के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया;
- (च) रजिस्ट्रार के पास शासी निकाय की वार्षिक सूची को प्रस्तुत करने हेतु फीस और विलम्ब फीस का उद्ग्रहण और धारा 34 के अधीन वार्षिक सूची के साथ प्रस्तुत किए जाने वाला प्ररूप और दस्तावेज;
- (छ) आय और व्यय के विवरण का प्ररूप और सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां तथा प्रभारित की जाने वाली फीस और ऐसे विवरण और विवरणियों को दाखिल करने हेतु विलम्ब फीस तथा सोसाइटी द्वारा रजिस्टर, लेखा बहियों एवं अन्य अभिलेख अनुरक्षित करने हेतु धारा 35 के अधीन अनुसरण में लाई जाने वाली प्रक्रिया;
- (ज) दस्तावेजों का निरीक्षण और धारा 36 के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीस;
- (झ) धारा 40 के अधीन प्रभारित की जाने वाली ब्याज की दर;
- (ञ) धारा 51 की उप-धारा (2) के अधीन अपील हेतु प्रक्रिया और ऐसी अपील के लिए फीस;
- (ट) अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु प्रक्रिया और धारा 54 के अधीन उसकी फीस का उद्ग्रहण;
- (ठ) धारा 55 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से पूर्व या पश्चात् विनिश्चयों, आदेशों, प्रविष्टियों या दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस; और
- (ड) कोई अन्य मामला जो राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु विहित किए जाने अपेक्षित है।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन

की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त क्रमवर्ती सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमन्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

छूट देने की
शक्ति।

57. राज्य सरकार लिखित में आदेश द्वारा,—

- (क) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध को लागू होने में छूट दे सकेगी; और
- (ख) निदेश दे सकेगी कि ऐसा कोई उपबन्ध उस विस्तार तक, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग को लागू होगा।

निरसन और
व्यावृत्तियाँ।

58. (1) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 88 के फलस्वरूप इसकी धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त और हिमाचल प्रदेश (विधियों का लागू होना) आदेश, 1948 और बिलासपुर (विधियों का लागू होना) आदेश, 1949 के फलस्वरूप प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का, जहां तक कि यह हिमाचल प्रदेश राज्य में लागू है, एतद्वारा निरसन किया जाता है।

1860 का 21

(2) हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त अधिनियम के अधीन किए गए निरसनों, जारी की गई अधिसूचना, जारी किया गया नियम, किया गया आदेश, की गई अपेक्षा, किया गया रजिस्ट्रीकरण, दिया गया प्रमाण-पत्र, दिया गया नोटिस, किया गया विनिश्चय, दिया गया निदेश, किया गया अनुमोदन, प्राधिकार, दी गई सम्मति, किए गए अनुरोध या यदि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ पर प्रवृत्त है, तो उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेंगी तथा इसी प्रकार प्रभावी होगी मानों वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई, जारी की गई या दी गई हो।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पूर्व विद्यमान प्रत्येक सोसाइटी जिसे इस अधिनियम या सोसाइटियों सम्बन्धी किसी अन्य प्रवृत्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत

किया गया है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझी जाएंगी तथा ऐसी सोसाइटी की उप-विधियां, जहां तक कि वे इस अधिनियम, या नियमों के उपबन्धों के असंगत न हों, उसी प्रकार प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक कि वे परिवर्तित या विखण्डित न की गई हों।

(4) उक्त अधिनियम के अधीन की गई समस्त नियुक्तियां, बनाए गए नियम और किए गए आदेश, जारी की गई समस्त अधिसूचनाएं और नोटिस तथा संस्थित समस्त वाद और अन्य कार्यवाहियां, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई, जारी की गई और संस्थित कि गई समझी जाएंगी।

(5) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ पर किसी न्यायालय में या रजिस्ट्रार या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लम्बित कोई विधिक कार्यवाही, उस न्यायालय में या रजिस्ट्रार अथवा उस प्राधिकारी के समक्ष जारी रहेगी मानों कि यह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया हो।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सोसाइटियों और उनके रजिस्ट्रीकरण से सम्बन्धित विधि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 21) द्वारा शासित (विनियमित) है। राज्य सरकार इस तथ्य से अभिज्ञ है कि जब से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अधिनियमित किया गया है तब से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक वातावरण तथा विकासदर्शन में भी अत्यधिक परिवर्तन आया है। राज्य ने मात्र विनियामक होने के कारण विकास सेवाओं, आर्थिक सहायताओं (सहायकियों), प्रोत्साहनों इत्यादि के प्रदाता की भूमिका अपनाई है तथा समाज की बड़े पैमाने पर भौतिक प्रगति के साथ संयोजन कर लिया है, समय बीतने के साथ अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध अप्रचलित हो चुके हैं। उक्त अधिनियम बहुत से आधारभूत मामलों जैसे रजिस्ट्रीकरण आदि के लिए ही उपबन्ध करता है तथा इन संगठनों के कृत्यकरण के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे शासी निकाय/साधारण निकाय, निर्वाचनों, विवाद समाधानों, नियन्त्रण और संतुलन की पद्धति और लोक जवाबदारी इत्यादि के विषय में मौन है। राज्य सरकार राज्य सिविल सोसाइटी भागीदारी और राज्य-कृत्यों के बढ़ते हुए समाजीकरण के उभरते हुए विकास प्रतिमान की बाबत जागरूक है जो राज्य सरकार को निरन्तर जानने, मार्गदर्शन करने, निदेश देने और मॉनीटर करने की आवश्यकता को अनुरेखित करती है कि कैसे इन न्यायगत कृत्यों को किया जा रहा है और क्या सोसाइटियों द्वारा वृहत् लोकहित की पूर्ति की जा रही है।

हाल में, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। राज्य सरकार इस तथ्य का समादर करती है कि अब सोसाइटियां न केवल सामाजिक, साहित्यिक या स्वैच्छिक कार्य के लिए अपितु शिक्षा, प्रशिक्षण और ग्रामीण विकास आदि के संवर्धन के क्षेत्र में मुख्यतः विभिन्न दाता संगठनों, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रस्थापित, निधिबद्ध या सम्प्रवर्तित की जा रही सेवाओं की अभिपूर्ति करने हेतु भी रजिस्ट्रीकृत हो रही है, जिससे वृहत् लोक सहभागिता, प्रकटीकरण और उत्तरदायित्व आवश्यक हो जाता है।

अतः हिमाचल प्रदेश राज्य में तथा लागू सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 को निरसित करने का और इन सोसाइटियों के कामकाज के समस्त पहलुओं को सम्मिलित करते हुए तथा विधिक ढांचे में कमजोरियों के कारण अनाचार की संभावनाओं को दूर करने हेतु एक बृहत् विधान अधिनियमित करने का विनिश्चय किया गया है तथा जो अन्य बातों के साथ,—

- (i) ऐसी सोसाइटियों के सदस्यता आधार के विस्तारीकरण के लिए;
- (ii) शासी निकाय/साधारण निकाय के कृत्यों को निर्धारित करने के लिए;
- (iii) ऐसी सोसाइटियों के कृत्यकरण में नियन्त्रण और सन्तुलन की प्रणाली के लिए; और
- (iv) निर्वाचनों, लेखा परीक्षा, विवाद समाधान और सम्बन्धित विषयों के लिए, उपबन्ध करेगा।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

कुलदीप कुमार,
प्रभारी मन्त्री।

शिमला:

तारीख..... 2006.

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक के उपबन्ध विद्यमान सरकारी तन्त्र के माध्यम से प्रवर्तित किए जाएंगे। इस प्रकार, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। विधेयक का खण्ड 55(2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई फीस, प्रभारों और अन्य राशियों को राज्य की संचित निधि में जमा करने का उपबन्ध करने के लिए है जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 56 इस अधिनियम के उपबन्ध को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन आवश्यक और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[नस्ति संख्या कोप-ए (2)2/99-(एस)]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2006 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 16 of 2006

**THE HIMACHAL PRADESH SOCIETIES REGISTRATION
BILL, 2006**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to re-enact the law to provide for the registration and working of literary, scientific, educational, religious, charitable or other Societies in the State of Himachal Pradesh and to repeal the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860) in so far as it is applicable to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty- seventh Year of the Republic of India, as follows:—

CHAPTER -I

PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006.

Short title, commencement and application.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

(3) This Act shall apply to Societies formed for all or any of the following purposes, namely:—

- (i) promotion of science, education, literature or fine arts;
- (ii) diffusion of useful knowledge;
- (iii) diffusion of political knowledge;
- (iv) foundation or maintenance of libraries or reading rooms for general use among the members or open to the public;

- (v) establishment and maintenance of galleries of paintings and other works of art;
- (vi) establishment and maintenance of public museums;
- (vii) collection of natural history, mechanical and philosophical inventions, instruments or designs;
- (viii) promotion of social welfare;
- (ix) promotion of religious or charitable purpose including establishment of funds for welfare of military orphans, welfare of political sufferers and welfare of the like;
- (x) promotion and implementation of different schemes sponsored by the State Government or the Central Government;
- (xi) promotion of Commerce, Industries and Khadi; and
- (xii) promotion of Rural Development.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Collector” shall mean the Chief-Officer-in-charge of the revenue administration of a district and shall include a Deputy Commissioner;
- (b) “family” means husband, wife and their unmarried sons and daughters;
- (c) “financial year” shall mean year commencing on the first day of April;
- (d) “general body” means all the member of the Society;
- (e) “general meeting” means meeting of the general body of a Society and includes special general meeting;
- (f) “Governing body” means the Governing body elected under section 15 of this Act and entrusted for the time being with the management of a Society under its regulation;
- (g) “Government” or “State Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (h) “member of the Society” means a person who has been admitted in the Society according to the regulations thereof, continues for the time being to be a member of the Society and,
 - (i) having paid subscription,
 - (ii) having signed the roll or list of members,
 - (iii) having not resigned,

in accordance with the regulations of the Society;

- (i) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (j) "Registrar" means the Registrar of Co-operative Societies appointed under sub-section (1) of section 3 and includes Additional, Joint, Deputy and Assistant Registrars of Societies, appointed under sub-section(2) of the said section when exercising or performing all or any of the powers or duties of the Registrar;
- (k) "regulations" or "bye-laws" means registered regulations or bye-laws of a Society for the time being in force;
- (l) "Society" means a Society registered under section 6 of this Act; and
- (m) "State Aided Society" means a Society which receives or has received aid, grant or loan or has received land, building or both on concessional rates and other facilities from the Central Government or the State Government or any Statutory body or any other agency located in India or abroad.

CHAPTER-II

REGISTRAR AND OTHER OFFICERS OF SOCIETIES

3. (1) The State Government may, by notification, appoint a person to be called the Registrar of Societies who shall exercise such powers and shall perform such duties and functions as are conferred by or under the provisions of this Act and shall, subject to such general or special orders as the State Government may make, superintend the administration and carry out the provisions of this Act.

Registrar and other officers of Societies.

(2) The State Government may, by like notification, appoint persons to be called Additional, Joint, Deputy and Assistant Registrars of Societies for such areas as may be specified in the notification and empower them to exercise powers and to perform duties under all or any of the provisions of this Act as may be specified in the notification.

CHAPTER-III

REGISTRATION

4. Any seven or more persons, being member of different families and competent to contract under section 11 of the Indian Contract Act, 1872, associated for any literary, scientific or charitable purpose as described in sub-section (3) of section 1 of this Act, may, by subscribing their names to a memorandum of association, and filing the same with the Registrar, form themselves into a Society under this Act.

Societies formed by memorandum of association and registration

Requirements
of
memorandum
of
association.

5. (1) The memorandum of association of every Society shall state—

- (i) the name of the Society;
- (ii) the objects of the Society;
- (iii) the location of the head office of the Society;
- (iv) the names, age, address and occupation of the Governors, Council, Directors or Governing body to whom by the regulation of the Society the management of its affairs is entrusted.

(2) No name shall be proposed in the memorandum of association—

- (a) as is identical with or too nearly resembles the name by which a Society in existence has been previously registered anywhere in the State; or
- (b) which has as its component—
 - (i) such words as may suggest or may be calculated to suggest the patronage of the Government of India or the Government of a State; or
 - (ii) such words of National, International or universal importance or such other words as the State Government may, from time to time, by notification, specify; or
 - (iii) such words as is, in the opinion of Registrar, likely to mislead the public.

(3) A copy of the regulations of the Society, certified to be a correct copy by not less than three of the members of the Governing body, shall be filed with the memorandum of association.

(4) The persons by whom or on whose behalf such memorandum is admitted shall furnish such further information in regard to the Society as the Registrar may require.

Registration.

6. If the Registrar is satisfied that a Society has complied with the provisions of this Act and the rules made thereunder and that its proposed regulations are not contrary to the said provisions, he shall register the Society and its regulations on payment of such fee as may be prescribed and shall issue a certificate of registration.

7. A certificate of registration signed by the Registrar shall be conclusive evidence that the Society mentioned therein is duly registered unless it is proved that the registration of the Society has been cancelled. Evidence of registration.

8. The regulations of a Society may provide for,—

Regulations of Society.

- (i) the conditions of admission of members;
- (ii) the liability of members to fines and forfeitures under certain circumstances;
- (iii) the consequences of non-payment of any subscription or fine, the resignation and expulsion of members;
- (iv) the appointment and removal of staff and officers and their powers;
- (v) the manner of electing and removing the Governing body and the powers of such body;
- (vi) the time and place of annual General meeting and other meetings of the Society;
- (vii) the manner in which notice of such meetings may be given;
- (viii) the quorum necessary for the transaction of business at meetings of the Society;
- (ix) the manner of making, altering and rescinding regulations;
- (x) the investment of funds, keeping of accounts and for an annual or periodical audit of accounts;
- (xi) the manner of dissolving the Society;
- (xii) the condition that the Society will have neither profit motive nor its profit shall be distributed among members;
- (xiii) the determination after dissolution that property be utilized by Government according to section 48;
- (xiv) matters to be provided by bye-laws and the manner in which they shall be made; and
- (xv) such other matters as may be considered expedient having regard to the nature and objects of the Society.

9. (1) No amendment of the memorandum of association or regulations of a registered Society shall be valid until the amendment has been registered under this Act. Amendment of memorandum or regulations or bye-laws of registered Society.

(2) Every proposal for such amendment shall be forwarded to the Registrar in such form together with such fee as may be prescribed and if the

Registrar is satisfied that the amendment is not contrary to this Act or the rules made thereunder, he may, if thinks fit, register the amendment.

(3) No proposal for amendment in the memorandum of association or regulations of a registered Society shall be entertained if such proposal has not been approved by a majority of three-fifth members present in the general meeting called for such purpose.

(4) Where an amendment is registered under sub-section (2), the Registrar shall issue to the Society, on payment of such fee as may be prescribed, a copy of the amendment certified by him which shall be conclusive evidence that the same is duly registered.

(5) Every Society registered under the Societies Registration Act, 1860 shall bring their bye-laws in conformity with the provisions of this Act and the rules made thereunder within a period of ninety days from the date of commencement of this Act: XXI of 1860

Provided that Registrar may, if satisfied, for the reason to be recorded in writing, allow further period not exceeding ninety days.

Change of
name of
Society.

10. Subject to the provisions of section 12, any registered Society may, with the consent of not less than two-thirds of the total number of its members, by a resolution at a general meeting convened for the purpose, change its name.

Notice of
change of
name.

11. (1) A copy of the resolution passed under section 10 shall be sent to the Registrar.

(2) If the Registrar is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with and that the proposed name is in conformity with the provisions of sub-sections (2) and (3) of section 5, he shall enter the new name in the register in place of the former one and issue a certificate of registration with necessary alterations embodied therein, and the change of name shall be complete and effective only on issue of such a certificate.

(3) The Registrar shall also make the necessary alteration in the memorandum of association of the Society.

(4) The Registrar shall charge fee, as may be prescribed, for any copy of certificate issued under sub-section (2) and all fees so paid shall be deposited into Government treasury.

12. The change in the name of the Society shall not affect any rights or obligations of either the members who were admitted prior to the change of the name of Society or render defective any legal proceeding by or against the Society. Effect of change of name.

13. Whenever it shall appear to the Governing body of any registered Society which has been established for any particular purpose or purposes that it is advisable to alter, extend or abridge such purpose to or for other purposes within the meaning of this Act, such Governing body may submit the proposition to the members of the Society in a written or printed report and may convene a special general meeting for the consideration thereof according to the regulations of the Society: Societies enabled to alter, extend or abridge their purposes.

Provided that no such proposition shall be carried into effect unless such report shall have been delivered or sent by post to every member of the Society, ten days previous to the special general meeting convened by the Governing body for the consideration thereof, and unless such proposition shall have been agreed to by the votes of three-fifth of the members, delivered in person or by proxy, and confirmed by the votes of three-fifth of the members present at a second special general meeting convened by the Governing body at an interval of one month after the former meeting.

14. Every Society shall be a body corporate by the name under which it is registered having perpetual succession and a common seal, and shall have powers to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, enter into contract, institute and defend suits and other legal proceedings and to do all other things necessary for the purpose for which it is constituted, and shall by the said name, sue or be sued. Society to be a body corporate.

CHAPTER-IV

MANAGEMENT OF THE SOCIETY, MEMBER'S RIGHTS AND PRIVILEGES

15. (1) Every Society shall elect a Governing body, consisting of not less than three members of the Society, by a resolution passed by a majority of the members present and entitled to vote at an annual general body meeting of the Society held under section 19. Governing body of the Society.

(2) The term of the Governing body or of its members so elected shall be as may be specified in the regulations but not exceeding three years:

Provided that a member of the Governing body of a Society shall be eligible for re-election as such, if the bye-laws so permit:

Provided further that a member of the Governing body may be removed by the general body in a meeting specially convened for such purpose by simple majority of votes of the members present after affording such member an opportunity of being heard.

(3) Every Society shall maintain a register showing the names, addresses and occupations of the persons, who are members of the Governing body and the President or Secretary or any person authorized in this behalf by Governing body, shall file with the Registrar—

- (i) a copy of the register within a period of fourteen days from the date of election of the members of the first Governing body; and
- (ii) a notice of every change in the members of the Governing body within a period of fourteen days from the date of such change.

(4) The management of every Society shall vest in a Governing body elected under sub-section.(1), which shall exercise such powers and perform such functions as may be conferred or imposed by this Act, the rules or the bye-laws.

Disquali-
fications.

16. A person shall be disqualified for being a member of the Governing body of a Society under this Act if, on the date of elections, he,

- (a) is disqualified for such appointment by an order of a Court or the Registrar for causing loss to the Society or retaining property of the Society or for any other reasons detrimental to the interest of the Society; or
- (b) is in arrears of prescribed subscription fee and a period of 45 days is over after delivering notice to such members to such effect; or
- (c) has been convicted of a cognizable offence and sentenced to a term exceeding 3 months; or
- (d) has incurred any of the disqualifications, as may be prescribed.

Supply of
copies of
Bye-laws.

17. Every Society shall, deliver a copy of its bye-laws, to each member of the Society at the time of admission.

Supply of
copies of
balance-
sheet etc.

18. Every Society shall supply to every member a copy of the balance-sheet or a statement of accounts together with the auditor's report at its annual general body meeting, if not supplied in advance.

Meetings.

19. (1) The bye-laws of the Society shall specify the frequency and the manner in which the meetings of the Governing body and general body shall be held, so however that the Governing body shall meet at least once in

every three months and general body shall meet at least once in a financial year.

(2) Every Society shall record in the minutes book, the minutes of all proceedings of every general body meeting and also every meeting of its Governing body.

(3) Such minutes shall be communicated to all the members invited for the meeting within thirty days of the said meeting.

20. (1) Every Society registered under this Act shall hold the annual general meeting of its members once in a financial year at which the report of management of the Society for the previous financial years together with an audited copy of the balance sheet, income and expenditure account and the auditor's report shall be submitted for approval.

Annual
general
meeting.

(2) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), the general meeting of a Society shall be held at least once in every financial year for the purpose of—

- (a) approval of the programme of activities of the Society prepared by the Governing body for the ensuing year;
- (b) election, if any, in the prescribed manner of the members of the Governing body other than the *nominated members*;
- (c) consideration of the audit report and the annual report; and
- (d) consideration of any other matter, which may be brought before, in accordance with the regulations of the Society.

(3) Such meeting shall be held not more than fifteen months after the date of the last preceding meeting held under sub-section(1).

(4) The first annual general meeting shall be held by a Society within fifteen months of its registration. The subsequent annual general meeting of the Society shall be held within twelve months after the first annual general meeting:

Provided that the Registrar may, for special reasons to be recorded in writing, extend the time within which an annual general meeting shall be held by a further period not exceeding three months.

(5) Quorum for general meeting shall be one-half of the total members or as provided in the bye-laws, whichever is more.

21. (1) A special general meeting shall be called at any time by the

Special
general
meeting.

President, or by a simple majority of the members of a Governing body, within one month—

- (a) on a requisition, containing the proposed agenda and reasons for such meeting, in writing of one-fifth of the members of a Society or of members, the number of which is specified in the bye-laws for the purpose, whichever is lower, or
- (b) at the instance of the Registrar.

(2) If a special general meeting of a Society is not called in accordance with the requisition referred to in sub-section (1), the Registrar or any person authorized by him in this behalf, shall call such meeting, and that meeting shall be deemed to be a meeting duly called by the Governing body.

(3) The Registrar shall have power to order that the expenditure incurred in calling a meeting under sub-section (2) shall be paid out of the funds of the Society or by such person or persons who, in the opinion of the Registrar, were responsible for the refusal or failure to convene the meeting.

(4) Quorum for special general meeting shall be same as provided for annual general meeting under sub-section (5) of section 19.

22. (1) The Governing body or any officer of the registered Society authorized in this behalf by its bye-laws, may bring or defend cause to be brought or defended any action or other legal proceeding touching or concerning any property, right or claim of the registered Society and may sue or be sued in respect of any such property, right or claim.

(2) Any action or legal proceedings shall not abate or be discontinued by the death; resignation or removal from office of any officer or member of the Society.

23. (1) The subscribers of the memorandum of association shall be the first members of the Society.

(2) Every Society shall maintain at its head office a register of its members and shall enter therein, the following particulars, namely:—

- (a) Name, address and signature with date, of each member;
- (b) the date on which the members are admitted; and
- (c) the date on which the members ceased to be members.

(3) The register of members shall be *prima facie* evidence of the membership of the Society and of all matters entered therein:

Provided that no member whose subscription for the time being is in arrear for a period exceeding six months shall be entitled to vote in any proceedings of the Society under this Act.

(4) If entries are not made in the register of members within thirty days of admission of a member or cessation of membership, every office-bearer in default shall be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

Legal
proceedings.

Register of
members.

(5) Subject to the approval of general body, a member may be expelled by the Governing body if he acts contrary to the interest of the Society.

24. (1) Any member of a registered Society who may be in arrear of a subscription which, according to the regulations of the Society, he is bound to pay or who possess himself of or detain any property of the Society in a manner or for a time contrary to such regulations or injure or destroy any property of the Society, may be sued for such arrear or for the damage occurring from such possession, detention, injury or destruction of the property in accordance with the provisions of this Act.

Members liable to be sued as strangers.

(2) If in any suit or other proceedings brought under sub-section (1) at the instance of the Society, the defendant shall be successful and shall be adjudged to recover his costs, he may elect to proceed to recover the same from the officer in whose name the suit or other proceedings shall be brought or from the Society, and in the latter case, shall have process against the property of the said Society in accordance with the provision of this Act.

25. Any member of the registered Society, who steal, purloin, embezzle any money or other property, or wilfully and maliciously destroy or injure any property of such Society, or forge any deed, bond, security for money receipt, or other instrument, whereby the funds of the Society may be exposed to loss, shall be subject to the same prosecution, and, if convicted, shall be liable to be punished in like manner as any person who is not a member, would be subject and liable to in respect of the like offence.

Members guilty of offences punishable as strangers.

26. Whenever by any bye-law duly made in accordance with the regulations of the Society, any pecuniary penalty is imposed for the breach of any regulation or bye-law of the Society, such penalty, when accrued, may be recovered in any Court, having jurisdiction where the defendant resides, or the office of the Society is situated, as the Governing body thereof shall deem expedient.

Recovery of penalty accruing under bye-law.

CHAPTER—V

PROPERTIES AND FUNDS OF SOCIETIES

27. The property, movable or immovable, belonging to a Society registered under this Act, shall be deemed to be vested in the general body of such Society and in all proceedings, civil or criminal, may be described as the property of the general body of such Society by their proper title.

Property of Society, how vested.

28. No immovable property shall be acquired or transferred by way of sale, gift or otherwise by the Society without the previous approval of its general body:

Restriction on transfer of property.

Provided that information relating to all such transactions of property shall also be passed on and got recorded with the Registrar within a period of fifteen days.

Suit by and
against
Societies.

29. Every Society may sue or be sued in the name of the President or Chairman or the Secretary or the Governing body, as the case may be, as shall be determined by the regulations of the Society and in default of such determination, in the name of such person as may be appointed by the Governing body for the occasion:

Provided that it shall be competent for any person having a claim or demand against the Society to sue the President or Chairman or the Secretary or the Governing body, if on application to the Governing body some other officers or person be not nominated to be the defendant.

Suit not to
abate.

30. No suit or proceeding in any civil court shall abate or discontinue by reason of the person by or against whom such suit or proceedings shall have been brought or continued, dying or ceasing to fill the character in the name where of he shall have sued or been sued, but the same suit or proceeding shall be continued in the name of or against the successor of such person.

Enforcement
of judgment
against
Society.

31. (1) If any judgment is passed against any officer or member of the registered Society, such judgment shall not be enforced against the property, moveable or immovable, or against the body, of such officer, but against the property of the registered Society.

(2) The application for execution shall set forth the judgment, the fact of the party against whom it shall have been passed having sued or having been sued, as the case may be, on behalf of the registered Society only, and shall require to have the judgment enforced against the property of the registered Society.

Books of
accounts to
be kept by
the Society.

32. (1) Every Society shall keep at its head office proper books of accounts in which shall be entered accurately—

- (a) all sums of money received and the source thereof, and all sums of money expended by the Society and the objects or purposes for which such sums are expended;
- (b) the assets and liabilities of the Society; and
- (c) details of immovable property acquired by the Society.

(2) The books of accounts shall be open to inspection by the office-bearer or members of the Society or the Registrar or the person authorized by the Registrar during the office hours.

(3) For the purpose of sub-section (1), proper books of accounts shall not be deemed to be kept with respect to the matters specified therein, if they do not give a true and fair view of the state of affairs of the Society and explain its transactions.

33. (1) Where the Registrar is satisfied that—

Powers of Registrar to seize records, etc.

- (a) the records, register or the books of accounts of a Society are likely to be tampered with or destroyed and the funds and the property of a Society are likely to be misappropriated or misapplied; or
- (b) if the Governing body of a Society is re-constituted at a general meeting of the Society and outgoing members of the Governing body refuse to handover charge of the records and property of the Society to those having to or entitled to receive such charge,

the Registrar may issue an order directing a person duly authorized by him in writing to seize and take possession of such books and records, funds and property of the Society and the officer or officers of the Society responsible for the custody of such books, records, funds and property shall give delivery thereof to the person so authorized.

(2) In order to secure compliance of the orders under sub-section (1), the Registrar may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used such minimum force including police force as may be considered necessary.

CHAPTER-VI

ANNUAL RETURNS, AUDIT, INSPECTION AND SUPERVISION

34. Once in every year, on or before the fourteenth day succeeding the day on which according to the regulations of the Society the annual general meeting of the Society is held or if the regulations do not provide for an annual general meeting, then within fourteen days of the 31st day of January, a list containing the full names, permanent addresses and chief occupations and others, if any, with signatures of the Governing body, shall be filed with the Registrar by the President or Secretary, in such form with such documents together with such fee as may be prescribed:

Annual list of Governing body to be filed.

Provided that the Registrar may, for reasons to be recorded in writing, grant further time not exceeding fifteen days for compliance:

Provided further that if the Society fails to file the list within the specified time limit or within the extended time, it may file the same within such further extended period but not exceeding 30 days and with such late fee as may be prescribed.

Audit.

35. (1) Every Society shall send to the Registrar a statement of income and expenditure with full particulars in such form as may be prescribed duly audited by its Auditors/Chartered Accountants audit report and balance sheet of the previous year alongwith details of all financial activities together with such fee as may be prescribed within ninety days from the date of annual general meeting of the Society or from 30th day of April, every year where the regulation do not provide for an annual general meeting. If the Society fails to send the aforesaid statements within the stipulated time the Society shall be liable to pay late fee as may be prescribed.

(2) On receipt of such statement, the Registrar shall verify the statements and shall ensure that the registers, account books and other records of the Societies are maintained in the prescribed manner and the funds have been utilized for the promotion of the Society and its objects and he may also issue such instructions in respect of utilization of funds as he may think fit:

Provided that accounts of Society having annual transaction exceeding one lac rupees shall be submitted to the Registrar duly audited by Chartered Accountant:

Provided further that Society having annual transaction exceeding five lac rupees shall publish, every year, its audited balance sheet including profit/loss account statement in a prominent local daily news paper.

(3) If the Registrar thinks necessary to undertake a special audit, he may audit, or cause to be audited by any person authorized by him by general or special order in writing in this behalf, the accounts of any Society.

(4) Any person authorized by general or special order, in writing in this behalf, by the Registrar shall, at all times, have access to all the books of accounts and other papers of a Society and every officer of the Society shall furnish such information in regard to the accounts and working of the Society as the person making such inspection may require.

Inspection
of
documents.

36. Any person may inspect all or any of the documents filed with the Registrar under this Act, or require copy or extract of any such document to be certified by the Registrar, by filing an application together with such fee as may be prescribed, and such certified copy shall be prima facie evidence of matters therein contained in all legal proceedings whatsoever.

Power to
enforce
attendance
etc.

37. The Registrar shall have power to summon and enforce the attendance of witnesses including the parties interested or any of them and to compel them to give evidence, and compel the production of documents by the same means and as far as possible in the same manner as provided in the Code of Civil Procedure, 1908.

38. (1) Where on perusing any document which a Society is required to submit to him under this Act, the Registrar is of opinion that any information or explanation is necessary in order that such document may afford full particulars of the matters to which it purports to relate, he may, by written order call on the Society submitting the documents to furnish in writing such information or explanation within such time as he may specify in the order.

Power of Registrar to call for information.

(2) On receipt of the order by the Society under sub-section (1), it shall be duty of the Society and all persons who are officers of the Society to furnish such information or explanation to the best of their power.

CHAPTER-VII

ENQUIRY AND SETTLEMENT OF DISPUTE

39. (1) The Registrar may, on his own motion or on an application made under sub-section(2), either by himself or by a person authorized by him, by order in writing, hold an enquiry into the constitution, working and financial conditions of a Society.

Enquiry by the Registrar.

(2) An enquiry under sub-section (1) shall be held on the application supported by an affidavit of—

- (a) a majority of the members of the Governing body of the Society; or
- (b) not less than one-third of the total number of members of the Society.

(3) The Registrar or the person authorized by him under sub-section (1) shall, for the purpose of an enquiry under this section, have the following powers, namely:—

- (a) he shall at all times have free access to the books, accounts, documents, securities, cash and other properties belonging to, or in the custody of the Society and may summon any person in possession, or responsible for the custody of any such books, accounts, documents, securities, cash or other properties to produce the same, if they relate to the head office of the Society at any place at the headquarters thereof and if they relate to any branch of the Society, at any place in the town wherein such branch thereof is located or in his own office;
- (b) he may summon any person who, he has reason to believe to have knowledge of any of the affairs of the Society to appear before him at any place at the headquarters of the Society or

any branch thereof or in his own office and may examine such person on oath;

- (c) he may, notwithstanding any regulation or bye-law specifying the period of notice for a general body meeting of the Society, require the officers of the Society to call a general body meeting of the Society at such time at the head office of the Society or any other place at the headquarter of the Society and to determine such matters as may be directed by him and where the officers of the Society refuse or fail to call such a meeting, he shall have power to call it himself; and
- (d) any meeting of the Society called under clause(c) shall have all the powers of a general body meeting called under the regulations or bye-laws of the Society and its proceedings shall be regulated by such bye-laws.

(4) When an enquiry is made under this section, the Registrar shall communicate the outcome of the enquiry to the Society and may issue appropriate directions to the Society, which shall be binding on all parties concerned.

Surcharge.

40. (1) Where, in the course of audit under section 35 or an enquiry under section 39, it appears that any person who had taken part in the establishment or management of the Society or any past or present President, Secretary, member or the staff of the Society; has misapplied or retained, or become liable or accountable for any money or property of the Society, or has been guilty of misfeasance or breach of trust in relation to the Society, the Registrar may, on a report received from the officer or an application received from the Governing body of the Society or his own motion, examine into the conduct of such person and after giving reasonable opportunity to the person concerned to submit his explanation, make an order requiring him to repay or restore the money or property or any part thereof, respectively with interest at such rate as may be prescribed or to contribute such sum to the assets of the Society by way of compensation in regard to the misapplication, retainer, misfeasance or breach of trust as the Registrar thinks just.

(2) Any sum ordered under this section to be repaid to a Society or recovered as a contribution to its assets, on a requisition being made in this behalf by the Registrar, shall be recovered as arrears of land revenue under the provision of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

(3) This section shall apply notwithstanding any criminal prosecution launched or proposed to be launched against such person.

Supersession
of Govern-
ing body.

41. (1) If, in the opinion of the Registrar, Governing body of any State Aided Society or any other Society engaged in delivering services to

public, such as education, health, sanitation etc.,—

- (a) persistently makes default or is negligent in the performance of the duties imposed on it by or under this Act, regulations or bye-laws of the Society or by any lawful order passed by the State Government or Registrar, or is unwilling to perform such duties; or
- (b) commits acts which are prejudicial to the interest of the Society or its members; or
- (c) is otherwise not functioning properly,

the Registrar may, by order in writing, remove the Governing body and appoint one or more Administrators to manage the affairs of the Society for a specified period not exceeding six months in the first instance:

Provided that where it is proposed to remove the Governing body of the Society exclusively on the ground that election to the Governing body were not held in accordance with the provisions of this Act or the regulations or bye-laws made thereunder, no action shall be taken under this sub-section unless the Registrar or an officer authorized by him in this behalf has convened a meeting of the general body for conducting the election thereto in accordance with the provisions of this Act, or the regulations or bye-laws made thereunder but has failed to get the new Governing body elected.

(2) No order under sub-section(1) shall be made unless the Governing body has been given a reasonable opportunity of being heard.

(3) The period specified in the order under sub-section(1) may be extended for further period of six months, for the reasons to be recorded in writing, by the Registrar, and thereafter no further period shall be extended.

(4) The Administrator(s) appointed under sub-section(1) shall, subject to the control of Registrar and to such instructions as he may, from time to time, give, have power to exercise all or any of the functions of the Governing body or of any officers of the Society, and to take all such actions as may be required in the interest of the Society:

Provided that Administrator(s) will enroll no new member and make no appointment.

(5) The Registrar may fix the remuneration payable to the Administrator(s), and the amount of such remuneration and other costs, if any, incurred in the management of the Society shall be payable from the funds of the Society.

(6) The Administrator(s) appointed under sub-section(1) shall, at the expiry of the period of appointment, arrange for the constitution of a new Governing body in accordance with the regulations of the Society.



(7) If there is difference of opinion between the general body of the Society and Administrator(s) appointed under sub-section(1) in respect of any matter, it shall be referred to the Registrar for decision and his decision thereon shall be final.

(8) During the period between the issuance of notice and the passing of an order removing the Governing body, the Governing body may be required by the Registrar to function under the supervision and with the approval of such authority as the Registrar may specify in this behalf and no order made or resolution passed or any other act performed by the Governing body, shall be effective unless it is approved by such specified authority.

(9) Where the Registrar, while proceeding to take action under sub-section(1) is of the opinion that suspension of the Governing body or any member during the period of proceedings is necessary in the interest of the Society, he may suspend, such Governing body or member, as the case may be, and where the Governing body is suspended, make such arrangements as he thinks proper for the proper management of the affairs of the Society till the proceedings are completed:

Provided that if the Governing body or member so suspended is not removed, it or he shall be reinstated and the period of suspension shall count towards its or his term.

Dispute
regarding
manage-
ment.

42. (1) In the event of any dispute arising among the Governing body or the members of the Society or its employees in respect of any matter relating to affairs of the Society, any member or Governing body or employee or ex-employee or ex-member of the Society may refer the dispute to the Registrar for decision, who may either decide the dispute himself or refer such dispute to any other officer for disposal.

(2) Dispute for the purpose of sub-section (1) shall also include matters relating to claim by or against the Society and any matter arising in connection with the election of Governing body.

CHAPTER-VIII

AMALGAMATION, DIVISION, DISSOLUTION AND WINDING UP OF SOCIETIES

Amalgam-
ation and
division of
Societies.

43. (1) Any two or more Societies may, by a special resolution of both or all such Societies, and confirmed by a like resolution at a second meeting of both or all such Societies, convened after an interval of one month after the first meeting, get amalgamated into one Society with or without any dissolution or division of the funds of any of the Societies with intimation to the Registrar.

(2) Any Society may, by a special resolution divide itself into two or more Societies, and such resolution shall contain proposals for the division of the assets and liabilities of the Society among the new Societies into which it is proposed to divide itself and may also specify the area of operation of, and the members, who will constitute each of the new Societies.

(3) An amalgamation or division in pursuance of this section shall not prejudice any right of a creditor of any Society which was a party to such amalgamation or division.

44. (1) A Society may, by a special resolution, determine that it shall be dissolved of and thereupon, with prior intimation to the Registrar, it shall be dissolved at the time specified in the resolution and all the necessary steps shall be taken for the disposal and settlement of the property of the Society, and its claims and liabilities according to the bye-laws, if any of the Society, and if there are no bye-laws to this effect in the manner as the general body may find expedient: Dissolution of Society and adjustment of its affairs.

Provided that in the event of any dispute arising among the members of the Governing body or the members of the Society, the adjustment of its affairs shall be referred to the court and the court shall make such order in the matter including appointment of liquidator as it deems fit:

Provided further that if the Central Government or any State Government is a member of, or a contributory to, any Society registered under this Act, such Society shall not be dissolved without the consent of the Government concerned.

(2) A Society dissolved under this section shall file with the Registrar a full report showing as to how the property has been disposed of.

45. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the Registrar may, by an order in writing, cancel the registration of any Society on any of the following grounds:— Power of Registrar to cancel registration in certain circumstances.

- (a) that the registered Society has contravened any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; or
- (b) that the registered Society is insolvent, or must necessarily become so; or
- (c) that the business of any such registered Society is conducted fraudulently or not in accordance with the bye-laws or the objects specified in the memorandum filed with the Registrar under section 4.

(2) If it appears to the Registrar that any registered Society is carrying on any unlawful activity or allow unlawful activity to be carried on within any premises under the control of the Society, the Registrar may hold an enquiry into the activities of such Society and in respect of every such enquiry, the Registrar shall have the same powers as are specified in sub-section (3) of section 39.

(3) If on an enquiry under sub-section (2), the Registrar is satisfied that any such Society has been carrying on any unlawful activity or has allowed any unlawful activity to be carried on within any premises under the control of the Society, he shall, after giving reasonable notice to the Society to show cause why the registration of the Society should not be cancelled and after considering the representations, if any, made on behalf of the Society, by order, cancel the registration of the Society and shall communicate the order of cancellation forthwith to the registered Society.

Explanation.— For the purpose of this section, an activity shall be deemed to be unlawful if such activity is an offence punishable under any provision of law for the time being in force.

46. If upon the dissolution of any Society, there remains after the satisfaction of all its debts and liabilities any property whatsoever, the same shall not be paid to, or distributed among, the members of the said Society or any of them, but shall be given to some other Society, to be determined by the votes of not less than three-fifths of the members present personally at the time of dissolution or in default, thereof, by the court specified in section 44.

47. Orders made under section 44 shall, on application, be enforced as follows:—

- (a) when made by a liquidator, by a civil court having local jurisdiction, in the same manner as a decree of such court; and
- (b) when made by the court on appeal, in the same manner as a decree of that court.

48. (1) It shall be lawful for the members of any Society dissolved under section 44 to determine by majority of votes of the members present or by proxy at the time of dissolution of such Society that any property whatsoever remaining after satisfaction of all its debts and liabilities shall be given to Government to be utilized for any of the purposes referred to in sub-section (3) of section 1.

(2) In the event of cancellation of the registration of Society under section 44, all the movable and immovable assets of the Society or its institutions

Upon
dissolution
no
member to
receive
profit.

Enforce-
ment of
order.

Determination
after
dissolution
that property
be utilized by
the
Government.

or centres shall vest in the State Government to the extent of assistance, grant, aid or donation that the Society may have received from Central or State Government or any of the statutory bodies; and it shall be the duty of the Collector of the district where the property is situated to take charge of the same on intimation of cancellation by the Registrar.

CHAPTER-IX

OFFENCES AND PENALTIES

49. If any Society or any person, referred to in section 35 or 38, Penalty.
entrusted with the management of affairs of a Society, is required to furnish any information or return—

- (i) wilfully refuses or without lawful excuse neglects to furnish such information or return which it knows, to be false; or
- (ii) wilfully furnishes or causes to be furnished any information or return which it knows, to be false; or
- (iii) refuses to answer or wilfully gives a false answer to any question necessary for obtaining any information required to be furnished under relevant section, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to two thousand rupees for each such offence.

50. (1) No court inferior to that of a Magistrate of the first class shall Cognizance
of offences.
try an offence punishable under this Act.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint made by the Registrar or any other person authorized in writing by him, by general or special order, in that behalf.

CHAPTER-X

APPEAL

51. (1) An appeal shall lie,—

Appeal.

- (a) if the order is made by the Registrar, appointed under sub-section(1) of section 3, either in original case or in appeal under clause (b), to the State Government;
- (b) if the order is made by the subordinate officers, appointed under sub-section(2) of section 3 or any other person, to the Registrar appointed, under sub-section (1) of section 3.

(2) An appeal under sub-section(1) shall be filed within sixty days of the date of communication of the order in such form and in such manner accompanied by such fee as may be prescribed:

Provided that the appellate authority may admit an appeal after the expiry of said period of sixty days if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within such period.

CHAPTER-XI

MISCELLANEOUS

Registrar
and other
officers
to be
public
servants.

52. Every officer or person exercising or authorised to exercise powers under this Act or the rules made thereunder shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1908.

45 of 1908

Indemnity.

53. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar or any person subordinate to him or acting under his authority in respect of anything done by or purporting to have been done by him in good faith under this Act.

No
Objection
Certificate
from the
Registrar.

54. (1) Any Society registered outside the State; but wishes to open its branch(s) in the State, shall obtain No Objection Certificate from the Registrar before opening of such branch and shall pay such fee as may be prescribed:

Provided that if such Society does not comply with the direction or order of the Registrar or the Government then No Objection Certificate shall be cancelled.

(2) The branch(s) of such Society shall be governed under the provisions of this Act.

Fees.

55. (1) The State Government may prescribe the fees chargeable for the following purposes, namely :—

- (a) for registration of Societies;
- (b) for inspection of documents in the custody of the Registrar;
- (c) for making or granting copies of orders, decisions, entries or documents, before or after registration; and
- (d) for such other matters as appear to the Government necessary to give effect to the purposes of this Act.

(2) All fees, charges and other sums paid to the Registrar or any officer of the Government in pursuance of this Act, shall be credited to the Consolidated Fund of the State.

56. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. Power to make rules.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the levy of registration fee under section 6;
- (b) form and the procedure to be followed for amendment of memorandum or regulations or bye-laws of registered Society and the fee to be charged under section 9;
- (c) the procedure and conditions for change the name of a Society and fee to be charged for issue of certificate under section 11;
- (d) the qualification or disqualifications for membership of the Governing body of a Society under section 16;
- (e) procedure for election of the members of the Governing body under section 20;
- (f) the levy of fee and late fee for submission of annual list of Governing body with Registrar and the form and documents to be submitted with the annual list under section 34;
- (g) form of statement of income and expenditure and returns to be furnished by a Society to the Registrar and fee to be charged and late fee for filing such statement and returns and the procedure to be followed under section 35 for maintenance of register, account books and other record by the Societies;
- (h) inspection of documents and the fees to be charged under section 36;
- (i) the rate of interest to be charged under section 40;
- (j) the procedure for appeal under sub-section (2) of section 51 and fee for such appeal;
- (k) procedure for granting No Objection Certificate and the levy of fees thereof under section 54;
- (l) the fees to be charged for granting copies of decisions, orders, entries or documents, before or after registration under section 55; and

- (m) any other matter which in the opinion of the State Government is required to be prescribed for the purpose of this Act.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule or agrees that the rules should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity or anything previously done under that rule.

Power to
exempt.

57. The State Government may by an order in writing,—

- (a) exempt any Society or class of Societies from the application of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder; and
- (b) direct that any such provisions shall apply to such Society or class of Societies to such extent as may be specified in the order.

Repeal and
savings.

58. (1) The Societies Registration Act 1860 (hereinafter called the 'said Act') as in force by virtue of section 88 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (Act No. 31 of 1966) in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 thereof and as applied to the areas which comprised in Himachal Pradesh immediately before the 1st day of November, 1966 by virtue of the Himachal Pradesh (Application of Laws) Order, 1948 and the Bilaspur (Application of Laws) Order 1949, is hereby repealed in its application to the State of Himachal Pradesh.

(2) Without prejudice to the provisions contained in the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 with respect to repeals, any notification, rule, order, requirement, registration, certificate, notice, decision, direction, approval, authorization, consent, application, request or thing made, issued, given or done under the said Act, shall, if in force at the commencement of this Act, continue to be in force and have effect as if made, issued, given or done under the corresponding provisions of this Act.

(3) Every Society, existing immediately before the commencement of this Act which has been registered under the said Act or under any other Act relating to Societies in force, shall be deemed to be registered under the corresponding provisions of this Act, and the bye-laws of such Society shall.

in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, or the rules, continue to be in force until altered or rescinded.

(4) All appointments, rules and orders made, all notifications and notices issued and all suits and other proceedings instituted under the said Act shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been respectively made, issued and instituted under this Act.

(5) Save as otherwise provided in this Act, any legal proceeding pending in any court or before the Registrar or any other authority at the commencement of this Act shall be continued to be in that court or before the Registrar or that authority as if this Act had not been passed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, the law relating to the Societies and their registration in Himachal Pradesh is governed by the Societies Registration Act, 1860 (Central Act XXI of 1860). The State Government is conscious of the fact that the social, economic and political environment and also the development philosophy has undergone tremendous change since the Societies Registration Act 1860 was enacted. The State from being a mere regulator has assumed the role of provider of development services, subsidies, incentives etc. and coupled with the large scale material progress of the Society, with the passage of time, various provisions of Act have become obsolete. The said Act provides for most basic matters such as registration etc. and is silent about many vital aspects of functioning of these organizations such as functions of Governing body/general body, elections, dispute resolutions, system of checks and balances and public accountability etc. The State Government is also aware of the emerging development paradigm – that of State – Civil Society partnership and increasing societization of State functions which underscores the need for State Government to continuously know, guide, direct and monitor as to how these devolved functions are being performed and whether larger public interest is being served by the Societies.

Of late, there has been upsurge in the number of Societies registered under the said Act. The State Government appreciates the fact that Societies are now being registered not only for social, literary or voluntary work but also in areas of education, training and promotion of rural development etc. primarily to implement the services being offered, funded or promoted by various donor organizations, Government of India or State Government which necessitates broader public participation, disclosure and accountability.

Hence it has been decided to repeal the Societies Registration Act 1860 in its application to the State of Himachal Pradesh and to re-enact a comprehensive legislation covering all aspects of functioning of these Societies and eliminate chances of malpractices due to infirmities in the legal framework, and which interalia provides for,—

- (i) broad basing the membership base of such Societies;
- (ii) laying down the functions of Governing body/general body;
- (iii) a system of checks and balances in functioning of such Societies; and
- (iv) for elections, audit, dispute resolution and related matters.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

KULDEEP KUMAR,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:

The, 2006

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill shall be enforced through the existing Government machinery. As such, there shall be no additional expenditure out of the State Exchequer. Clause 55(2) of the Bill seeks to provide for credit of the fee, charges and other sums, realized under this Act, to the Consolidated Fund of the State which cannot be quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 56 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the provision of this Act. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[File No. Coop-A (2)2/99-(S)]

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Societies Registration Bill, 2006, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.